मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

सितम्बर-अक्टूबर 2017

संरक्षक
गोपाल भार्गव
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रबंध सम्पादक
शमीम उद्दीन

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

खास खबरें : मध्यप्रदेश के सभी गाँव और शहर खुले में शौच से मुक्त किये जाएंगे 5

आलेख : एक नई चेतना का संचार हुआ है स्वच्छता सेवा अभियान से 12

स्वच्छता ही सेवा : लेख : स्वच्छता ही है सच्ची मनुष्यता 14

स्वच्छता : जन-जन जुड़ा 'स्वच्छता ही सेवा' और 'जल रोको अभियान' में 16

उपलब्धि : होशंगाबाद जिला खुले में शौच से पूर्णतः मुक्त 18

स्वच्छता : साझा प्रयासों से शत-प्रतिशत स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करेंगे 21

आवास : प्रदेश में एक लाखवां आवास हितग्राही सम्मानित 24

मनरेगा : **अच्छी पहल** : मनरेगा की रेशम योजना से आय हो गई चौगुनी 26

पंचायत : **नवाचार** : पूर्ण स्वच्छ पेयजल की पहली अनूठी पंचायत बनी कोदरिया 32

अनुकरणीय : युवा सोच से सच होते सपने 33

आजीविका - सफलता की कहानी : स्व-सहायता समूह के सहयोग एवं मेहनत... 34

विभागीय : अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीडियो... 38

पंचायत गजट : 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलाया जायेगा स्वच्छता ही सेवा... 42

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का अगस्त अंक पढ़ा। इस अंक में संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत प्रदेश के गाँवों को स्वच्छ, बेरोजगारी मुक्त करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई है। संकल्प से सिद्धि अभियान के जरिए आमजन को सरकारी गतिविधियों से जोड़ने की पहल सराहनीय है। संकल्प से सिद्धि अभियान से स्वस्थ, स्वच्छ, आत्मनिर्भर और बेरोजगारीमुक्त ग्रामीण भारत के निर्माण का सपना साकार होगा।

- वीरेन्द्र सिंह राजपूत
जबलपुर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का अगस्त माह का अंक मिला। संकल्प से सिद्धि अभियान पर केन्द्रित इस अंक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों और आदेशों को प्रकाशित किया गया है। इन आदेशों के प्रकाशन से न केवल ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों को शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी मिलती है, अपितु मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है।

- महेश साहू
खरगौन, (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का अगस्त माह का अंक पढ़ा। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कई गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों से अब तक कई ग्रामीण विशेषकर महिलायें लाभान्वित हो रही हैं। इस अंक में उन्हीं में से कुछ सफल महिला और स्व-सहायता समूहों की कहानी प्रकाशित की गई। ये कहानियाँ अन्य लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए प्रेरित करेंगी।

- अनीता विश्वकर्मा
सागर, (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ने को मिला। अंक में म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। जैविक खेती के जरिए किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आजीविका मिशन द्वारा किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए जैविक बीज एवं खाद के साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह एक सराहनीय प्रयास है।

- किशोर सिंह
सीहोर, (म.प्र.)

मंत्री जी का मार्गदर्शन

जीवन के संवर्धन का आधार है स्वच्छता और जल

प्रिय पाठकगण,

जीवन का आधार यदि जल है तो उसका दीर्घ जीवन स्वच्छता है। संपूर्ण प्रकृति के संवर्धन के लिए, इन आधार तथ्यों को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रव्यापी 'स्वच्छता ही सेवा' और 'जल रोको अभियान' चलाया गया।

प्रकृति के संवर्धन के लिए जल का व्यापीकरण जरूरी है। जल के व्यापीकरण का अर्थ है जल को कण-कण में होना चाहिए। यदि जल कहीं से रिस रहा है तो प्रकृति में धरती के किसी हिस्से से जल कम हो रहा है। इस वर्ष वैसे भी बारिश कम हुई है। अतः बहते जल को रोकना जरूरी है। जहां जल नहीं है वहां जीवन की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह है? आज सौर मण्डल के हजारों लाखों ग्रह जीवनविहीन हो गए हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि जल को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता हो। जल बेकार बहकर या हमारी अज्ञानता से रिसकर धरती से न रीत जाए।

हमारा दायित्व जल रोकने तक ही सीमित नहीं रहता, जल रोकने से जीवन की संभावनाएं तो बनेंगी लेकिन जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए और दीर्घजीवी बनाने के लिए स्वच्छता जरूरी है।

स्वच्छता जल की, स्वच्छता थल की और स्वच्छता सारे परिवेश की। हम कोशिश करें कि न तो जल में कोई गंदगी जाए न धरती पर कोई गंदगी बिखरे, हमारे घर, हमारे आँगन, हमारी गलियाँ साफ रहें। इस स्वच्छता के लिए हमें कई स्तरों पर काम करना होगा। स्वच्छता का यह अभियान हमारे दिवस मनाने और पखवाड़ा मनाने के साथ हमारी सोच में समाए। हमारे जीवन का हिस्सा बने। हम खुद तो साफ-सुथरे रहें, माहौल को भी साफ सुथरा रखें। इसके साथ-साथ समूचे समाज को साफ-सुथरा रहने के लिए प्रेरित करें।

भारत की बुनियाद गाँव हैं। हमारे गाँव, स्वच्छता को लेकर एक बड़ी चुनौती हैं। गाँव में स्वच्छता के लिए कई तरह के कार्यों की आवश्यकता है। सबसे पहले घर-घर में शौचालय बने, हम अपने गाँव को खुले में शौच से मुक्त बनाएं।

गाँव में यहाँ-वहाँ फैले कचरे की कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसका खाद बनाने में या बिजली बनाने में उपयोग हो सके। नई तकनीक के आधार पर गाँवों में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने का प्लांट लगे। इससे बिजली उत्पन्न होने के साथ कचरे का सुचारु प्रबंधन हो जाएगा।

मुझे लगता है कि स्वच्छता ही सेवा और जल रोको अभियान से प्रदेश भर में जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर चेतना का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदकर प्रेरक प्रसंग निर्मित किया, जिसका प्रभाव प्रदेश भर में हुआ और दो लाख से अधिक ट्विनपिटों का निर्माण हुआ। लोगों ने पूरे मनोयोग से इसमें भाग लिया। अब इस अभियान से आरंभ कार्यों को निरंतर रखना जरूरी है तभी प्रदेश पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त होगा। उम्मीद है सबके साझे प्रयास से प्रदेश प्रकृति के संवर्धन के लिए जल संरक्षण और स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता को आत्मसात करेगा।

इसी अपेक्षा के साथ।

भविष्य में यह संवाद निरन्तर रहेगा। पंचायिका में प्रकाशित योजनाओं का लाभ अवश्य लें।

शुभकामनाओं सहित।

(गोपाल भार्गव)

मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

संचालक की कलम से

स्वच्छता ही सेवा और जल रोको अभियान

प्रिय पाठको,

स्वच्छ भारत मिशन की तीसरी वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक जनभागीदारी से 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' आयोजित करने का आह्वान किया है। इस बार अल्प वर्षा हुई है अतः पानी के एक-एक कण को संचित करने और बहते जल को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'स्वच्छता ही सेवा' के साथ 'जल रोको अभियान' चलाने का भी आह्वान किया।

15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलाये गये स्वच्छता ही सेवा और जल रोको अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर 15 सितम्बर को किया। अभियान का शुभारंभ प्रदेश के सभी 51 जिलों 313 ब्लॉक मुख्यालयों में एक साथ किया गया। आयोजन में स्थानीय मंत्री, सांसद, विधायकगण, जिला तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में आमजनों की सक्रिय भागीदारी रही। प्रदेश भर में एक साथ दोपहर 3.35 मिनिट पर स्वच्छता की शपथ ली गई।

17 सितम्बर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन पूरे प्रदेश में ट्विनपिट की तकनीक से शौचालय निर्माण के लिए श्रमदान से गड्ढे खोदे गये। गड्ढे खोदने के कार्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव सहित सभी जनप्रतिनिधियों तथा आमजनों द्वारा भी भाग लिया गया। इस दिन लगभग 2,16,074 गड्ढे खोदे गये। अभियान अवधि में एक लाख शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त जल संरक्षण के लिए श्रमदान किया गया, जिसमें कई नदियों तथा स्थानीय जल संरचनाओं पर बोरी बंधान का कार्य और बहते जल को रोकने का प्रयास किया गया। सेवा दिवस पर प्रदेश की 22,816 ग्राम पंचायतों के कार्यालय में 'टायलेट एक प्रेम कथा' फिल्म का प्रसारण ग्रामीणजनों के लिए किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए स्वच्छता रथ यात्रा निकाली गयी। जिसमें कुल 650 स्वच्छता रथों को अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंचाने की व्यवस्था की गई। 18 से 24 सितम्बर तक व्यापक जनभागीदारी से प्रत्येक ग्राम में सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक संस्थाओं और परिसरों की साफ-सफाई की गयी। शौचालय निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया और खुले में शौच नहीं करने की शपथ दिलाई गई।

25 सितम्बर को सभी ग्रामों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्रामसभा में शौचालय निर्माण और गाँव की साफ-सफाई को लेकर चर्चाएं की गईं। 26 सितम्बर से 30 सितम्बर की अवधि में प्रभात फेरियाँ निकाली गयीं, कला मंडलियों, भजन मंडलियों द्वारा स्वच्छता को लेकर प्रेरक प्रस्तुतियाँ दी गयीं।

दो अक्टूबर को गाँधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में स्वच्छ भारत दिवस समारोह आयोजित किया गया। इन आयोजनों में खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 1269 सरपंचों, 936 बाल टोलियों, 973 भजन मंडलियों, 3807 सफाई कर्मियों तथा 3130 किशोर बालिकाओं को मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान से सम्मानित कर पुरस्कृत किया गया। इसी दिन होशंगाबाद और शाजापुर जिला तथा अन्य जिलों के 751 गाँव तथा 397 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त घोषित किये गये।

मध्यप्रदेश पंचायिका का यह अंक 'स्वच्छता ही सेवा' और 'जल रोको अभियान' पर केन्द्रित है। इसके अतिरिक्त कुछ नवाचार और सफलता की कहानियाँ भी शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए मार्गदर्शन और पंचायत गजट के निर्देश निश्चित ही आपके लिए उपयोगी होंगे।

कृपया पंचायिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपनी प्रतिक्रिया पत्रों के माध्यम से अवश्य भेजें।

(शमीम उद्दीन)
संचालक, पंचायत राज

स्वच्छता ही सेवा

मध्यप्रदेश के सभी गाँव और शहर खुले में शौच से मुक्त किये जाएंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितम्बर को इंदौर में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के तहत ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2016 में इंदौर प्रथम स्थान पर आया है। इसके लिये इंदौर की जनता बधाई की पात्र है। मध्यप्रदेश शासन के लिये भी यह गर्व की बात है। देश में स्वच्छता में नंबर वन आना आसान नहीं है। इसलिये नंबर वन बने रहने के सतत् प्रयास किये जायें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम आये हैं। वर्ष 2019 तक मध्यप्रदेश के सभी ग्रामों और शहरों को खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा। स्वच्छता एक आंदोलन है। जनता की सोच में बदलाव लाकर जनता के सहयोग से ही यह आंदोलन सफल हो सकता है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर शहर में स्वच्छता अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2016 में देश के 100 चयनित शहरों में से 22 शहर मध्यप्रदेश के हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बन जाने से ही काम नहीं चलेगा, उसका उपयोग करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्लास्टिक की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि प्लास्टिक से सर्वाधिक कचरा फैलता है और प्लास्टिक जल्दी नष्ट भी नहीं होता है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इंदौर मध्यप्रदेश के विकास का इंजन है। उद्योग, व्यापार और साफ-सफाई सहित हर क्षेत्र में इंदौर नंबर वन रहा है। इंदौर में नरसीमुंजी, टीसीएस और इंफोसिस जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं आ गई हैं और अपना

- **वर्ष 2019 तक मध्यप्रदेश के सभी ग्राम और शहर खुले में शौच से मुक्त होंगे।**
- **देश में नंबर वन बने रहने के लिए सतत् प्रयास जरूरी।**
- **प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी।**
- **इंदौर में पिछले डेढ़ वर्ष में 50 प्रतिशत वायु प्रदूषण घटा।**

व्यापार-व्यवसाय फैला रही हैं।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ ने कहा कि इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी बिन्दुओं पर खरा उतरा है। नवंबर 2016 से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन से इंदौर में साफ-सफाई विशेष रूप से परिलक्षित हुई है। इस अभियान में विद्यार्थियों, शिक्षकों, व्यापारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, समाजसेवी संगठनों आदि का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इंदौर में गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग कलेक्शन किया जा रहा है। गीले कचरे से जैविक खाद बनाई जा रही है। औसतन रोज 50 टन कचरा इकट्ठा हो रहा है। गीले कचरे से आने वाले समय में जैविक खाद के अलावा मिथेन गैस भी इकट्ठा की जाएगी, जिससे नगरीय सेवा की बसें चलेंगी और बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा परमाणु तकनीकी से स्लज कचरे से खाद बनाई जाएगी। पिछले डेढ़ वर्ष में विशेष साफ-सफाई अभियान से वायु प्रदूषण 50 प्रतिशत तक घट गया है। खान और सरस्वती नदी की सफाई का अभियान जारी है। खान नदी में गिरने वाले गंदे नालों की टेपिंग का कार्य तेजी से चल रहा है।

उत्कृष्ट कार्यों के लिये सम्मान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये समाजसेवियों, व्यापारी संगठनों और सरपंचों को सम्मानित किया। समारोह में हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्णमुरारी मोघे, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कविता पाटीदार, विधायकगण सर्वश्री महेन्द्र हार्डिया, राजेश सोनकर, सुदर्शन गुप्ता, सुश्री उषा ठाकुर तथा अपर मुख्य सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया, गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और सरपंच सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

रायसेन जिले को

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 17 सितम्बर को रायसेन जिले के ग्राम रतनपुर में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के तहत प्रदेश भर में चलाये जा रहे शौचालय के लिए गड्ढा खोदने के अभियान में शामिल हुए। उन्होंने साँची-रायसेन मार्ग पर ग्राम रतनपुर में ट्विन-पिट खोदने की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गाँवों को स्वच्छ रखने के लिये "स्वच्छता ही सेवा" अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में आज ही दो लाख गड्ढे खोदने का लक्ष्य है। आगामी 19 नवम्बर तक पूरे रायसेन जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस के अवसर पर स्वच्छता को प्राथमिकता देने वाले कार्य शुरू किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान अब

उन्नीस नवम्बर तक ओडीएफ करने का लक्ष्य

सीधे आमजन से जुड़ा अभियान बन गया है। मध्यप्रदेश की जनता भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग ले रही है।

प्रदेश में जिन क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, उनमें अभियान के तहत विशेष प्रयास किये जाएंगे।

श्री चौहान ने कहा कि खुले मे शौच जाना बीमारियों को बढ़ावा देना है। जहाँ स्वच्छता है, वहीं स्वस्थ जीवन है। उन्होंने प्रदेश के शौचालयविहीन घरों में रहने वाले परिवारों से शौचालय बनवाने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेशवासी खुले में शौच नहीं जाने का संकल्प लें। तभी स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत का निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर स्वच्छता रथ को हरी झण्डी दिखाकर गाँव-गाँव, घर-घर जाने के लिये रवाना किया। जिले के प्रभारी मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, साँची जनपद अध्यक्ष श्री एस. मुनियन, नगर पालिका अध्यक्ष श्री जमना सेन, अपर मुख्य सचिव श्री आर.एस. जुलानिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।

- **प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्म-दिवस पर "स्वच्छता ही सेवा" अभियान शुरू।**
- **रायसेन जिले को 19 नवम्बर तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य।**
- **17 सितम्बर को प्रदेश में शौचालय निर्माण के लिए दो लाख गड्ढे खोदने का लक्ष्य।**

श्री अमिताभ बच्चन ने की मध्यप्रदेश में स्वच्छता अभियान की सराहना

महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में जनभागीदारी से चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान की सराहना की है। दो अक्टूबर को एक टी.वी. चैनल पर स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान से बातचीत की।

श्री अमिताभ बच्चन ने पिछले एक साल में स्वच्छता अभियान के कारण आये बदलाव के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के सौ शहरों में मध्यप्रदेश के 22 शहर चुने गये। पूरे देश में इन्दौर नम्बर एक और भोपाल नम्बर दो पर रहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश आगे चल रहा है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर पूरे देश में नम्बर एक पर है।

प्रदेश में स्वच्छता अब जन-अभियान बन गया है। यह काम समाज के सहयोग के बिना सरकार अकेली नहीं कर सकती। जनता में जुनून है कि स्वच्छता के मामले में देश में सबसे आगे रहेंगे। श्री चौहान ने श्री अमिताभ बच्चन को बताया कि 378 शहरी निकाय पूरी तरह खुले में शौच जाने से मुक्त हो चुके हैं। स्वच्छता के प्रति मानसिकता बदलने का काम चल रहा है। गाँव-गाँव में भजन मंडलियों और अन्य माध्यमों द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। शौचालय का उपयोग करने की मानसिकता बनाने के लिये भी प्रयास तेज कर दिये हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महानायक को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण में शुरुआत में प्रदेश पीछे था, लेकिन बहुत कम समय में तेजी से काम करते हुए राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में आम नागरिकों के भरपूर सहयोग और समर्थन को देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्ष 2018 तक मध्यप्रदेश राज्य खुले में शौच से मुक्ति पा लेगा।

कई शहरों में चमत्कारी परिणाम मिले हैं। गंदगी से होने वाली बीमारियों का प्रकोप कम हुआ है। लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है। लोगों में अपने गाँव और अपने शहरों को स्वच्छ रखने की सकारात्मक मानसिकता बनी है। श्री चौहान ने लोगों को इस स्वच्छता अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी करने के लिये धन्यवाद भी दिया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता अब जन-अभियान बन गया है। यह काम समाज के सहयोग के बिना सरकार अकेली नहीं कर सकती। जनता में जुनून है कि स्वच्छता के मामले में देश में सबसे आगे रहेंगे। श्री चौहान ने श्री अमिताभ बच्चन को बताया कि 378 शहरी निकाय पूरी तरह खुले में शौच जाने से मुक्त हो चुके हैं। होशंगाबाद और शाजापुर जिलों को दो अक्टूबर को ही खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है।

श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता के प्रति मानसिकता बदलने का काम चल रहा है। गाँव-गाँव में भजन मंडलियों और अन्य माध्यमों द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। शौचालय का उपयोग करने की मानसिकता बनाने के लिये भी प्रयास तेज कर दिये हैं। मुख्यमंत्री ने बताया की जबलपुर में 10 मेगावॉट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू हो गया है। कचरे के निष्पादन के लिये व्यवस्थित इंतजाम किये गये हैं। प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। धीरे-धीरे जागरुकता बढ़ रही है। जनता और सरकार दोनों मिलकर स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं।

स्वच्छता ही सेवा और जल रोको अभियान

- **जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ स्वास्थ्य होता है।**
- **वर्ष 2022 तक हर गरीब का शौचालय युक्त अपना मकान होगा।**
- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्म दिवस 17 सितम्बर सेवा दिवस के रूप में मनाया गया।**
- **मुख्यमंत्री ने छतरपुर जिले के राजनगर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कनेरी में गनपत आदिवासी के घर शौचालय का गड्ढा खोदकर श्रमदान किया।**

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले के ग्राम कनेरी में स्वच्छता ही सेवा एवं जल रोको अभियान में शामिल हुए।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितम्बर को छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत सूरजपुर के ग्राम कनेरी पहुँचकर हितग्राही गनपत आदिवासी के आवासी शौचालय के निर्माण के लिये श्रमदान किया और "स्वच्छता ही सेवा" का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्म-दिन प्रदेश में सेवा-दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

ग्राम कनेरी में "स्वच्छता ही सेवा" और "जल रोको" अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घर-घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। शौचालय नहीं होने से बीमारियाँ फैलती हैं। घर की मान-मर्यादा भंग होती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छता अभियान चलाकर घर-घर शौचालय बनवाए जाएं। जन-प्रतिनिधि भी इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग करें। श्री चौहान ने लोगों से कहा कि अपने गाँव एवं घर को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि छतरपुर जिले में इस वर्ष बारिश 50 प्रतिशत से भी कम हुई है। इस कारण सूखे का संकट संभव है। सूखे के इस संभावित संकट के निराकरण के लिये राज्य सरकार हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित गनपत आदिवासी के घर के सामने शौचालय बनवाने के लिए भूमि पूजन किया और शौचालय का गड्ढा खोदकर श्रमदान किया। हितग्राही गनपत आदिवासी, हरी आदिवासी, हुलासी आदिवासी एवं जनकरानी के आवासों का निरीक्षण कर हितग्राहियों से चर्चा की। श्री चौहान ने यहीं पौध-रोपण भी किया और 32 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्टॉल में पहुँचकर स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की जानकारी भी ली।

कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती ललिता यादव, विधायक कुंवर विक्रम सिंह, श्री मानवेन्द्र सिंह, श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, श्रीमती रेखा यादव, श्री आर.डी. प्रजापति, बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश प्रजापति, पूर्व विधायक श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला, श्री उमेश शुक्ला, पूर्व सांसद श्री जीतेन्द्र सिंह बुंदेला, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह, श्री घासीराम पटेल सहित अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री राधेश्याम जुलानिया उपस्थित थे।

'स्वच्छता ही सेवा' राष्ट्रव्यापी अभियान
जल संरक्षण जनभागीदारी से ही संभव होगा

स्वच्छ भारत मिशन के तीन साल 2 अक्टूबर को पूर्ण होने पर भारत सरकार ने स्वच्छता ही सेवा राष्ट्रव्यापी अभियान का शंखनाद किया है। सागर जिले में स्वच्छता ही सेवा और जल रोको अभियान का शुभारंभ गढ़पहरा ग्राम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने किया।

15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक होने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा तथा की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा दी गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के राज्य कार्यक्रम अधिकारी श्री अतुल श्रीवास्तव ने प्रदेश के 51 जिलों में से 11 जिलों, 313 जनपद पंचायतों में से 51 जनपद पंचायतों के खुले में शौच मुक्त होने की जानकारी दी।

गढ़पहरा के हनुमान मंदिर प्रांगण से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत 17 दिनों के भीतर सागर जिले में 10,000 शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जल संरक्षण को कारगर बनाने के लिये जल रोको अभियान के तहत सागर जिले की लगभग 750 पंचायतों में बोरी बंधान का कार्य भी किया गया। कार्यक्रम में श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि अगर समय पर पानी के प्रवाह को रोक लिया गया तो भू-जल स्तर में सकारात्मक वृद्धि होगी जो फरवरी-मार्च माह तक हमारे पीने, फसल सिंचाई के लिये पर्याप्त होगा। पानी के स्तर को देखते हुए कृषक उन फसलों का चयन करें जो कम पानी की मांग करती हैं।

स्वच्छता को सर्वोपरि मानते हुए श्री भार्गव ने कहा कि शौचालय निर्माण करना हमारा कर्तव्य है जो हमारी महिलाओं का सम्मान बनाये रख सकता है।

सागर जिला प्रदेश में आवास निर्माण मामले में दूसरे स्थान पर है इसे अग्रणी बनाने के लिये अगले साल तक 15 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। गढ़पहरा को श्री भार्गव की ओर से 25 लाख रुपये की धर्मशाला एवं 50 लाख रुपये की सड़क निर्माण की सौगात भी मिली। आयोजन में स्वच्छता का संकल्प श्री भार्गव द्वारा दिलाया गया।

नरयावली विधायक श्री प्रदीप लारिया ने कहा कि शौचालय निर्माण कर लेना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उसका उपयोग भी किया जाना सुनिश्चित होना चाहिये। इसके लिये व्यवहार परिवर्तन किया जाना महत्वपूर्ण पहलू है। कोई भी अभियान जन समुदाय की सहभागिता से ही सफल होता है।

सागर कलेक्टर श्री आलोक कुमार सिंह ने कहा कि सभी के सहयोग से ही लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता मिल सकेगी। जल संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है और कम खर्चे में गढ़ाकोटा स्टापडेम एक उदाहरण है। अल्प वर्षा ने निश्चित ही थोड़ी परेशानी बढ़ाई है लेकिन किसान पहले से सोच विचार कर ही फसल का चयन करें।

स्वच्छता के विषय पर श्री सिंह ने कहा कि गढ़पहरा के इस पवित्र प्रांगण से शुभारंभ किया जाना हम सबको अपनी क्षमता का अहसास दिलायेगा और हम 10,000 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं के सम्मान की रक्षा और बीमारी से बचाव कर सकते हैं। आयोजन के दौरान गढ़पहरा के पास नाले पर जल संरक्षण हेतु बोरी बंधान का कार्य किया गया। इस अवसर पर बण्डा विधायक श्री हरवंश सिंह राठौर, गृह मंत्री प्रतिनिधि श्री अशोक सिंह बामोरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती तृप्ति सिंह, जनपद पंचायत अध्यक्ष सागर, सीईओ श्रीमती मंजू खरे, सदस्य, सचिव एवं अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

श्री गोपाल भार्गव ने श्रमदान कर खोदा शौचालय का गड्ढा

स्वच्छ भारत मिशन की तीसरी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित करने का आह्वान किया। मध्यप्रदेश में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जनप्रतिनिधियों, संभाग आयुक्तों, जिला कलेक्टरों तथा जिला पंचायत अध्यक्षों को विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करने के लिए कहा।

इस अभियान में प्रदेशव्यापी आयोजन किये गये सभी 51 जिलों तथा विकासखण्डों में अभियान का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्रवार माननीय मंत्री, सांसद, विधायक तथा जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे। अभियान के शुभारंभ के साथ ही शौचालय निर्माण के लिए प्रदेश भर में गड्ढे खोदे गये। स्थानीय स्तर पर जल रोकने के विभिन्न प्रयास भी किये गये। आयोजनों की श्रृंखला के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने जनपद पंचायत रहली अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदी में स्वच्छता ही सेवा तथा जल रोको अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री भार्गव ने शौचालय निर्माण के लिए गड्ढे को खोदकर मिट्टी निकाली। उन्होंने 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे जल रोको कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि शौचालय निर्माण तथा रखरखाव स्वयं हितग्राही करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता जरूरी है।

श्री भार्गव ने यह भी बताया कि इस वर्ष कम बारिश हुई है इससे आने वाले समय में जल संकट की स्थिति बन सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा पानी बचाने का अभियान चलाया जा रहा है। अतः आप सभी अपने-

अपने क्षेत्र के पानी के स्रोतों का संरक्षण करें। कार्यक्रम को जनपद पंचायत अध्यक्ष ने भी संबोधित किया।

● **ममता राय**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

एक नई चेतना का संचा

मध्यप्रदेश में इस साल 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चला। यद्यपि इस अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के सभी आयामों की ओर समाज का ध्यान दिलाया गया। यह अभियान शौचालयों के निर्माण पर अपेक्षाकृत कुछ अधिक केन्द्रित था। इसका कारण यह है कि सड़कों पर, सड़कों के किनारे में फैले कचरे, कागजों अथवा अन्य प्रकार की गंदगी से क्षति कई गुना अधिक खुले में शौच और उससे उत्पन्न गंदगी से होती है। इसीलिए 15 सितम्बर से जब अभियान की शुरुआत हुई तब से सबसे पहले घरों में और गाँव के सार्वजनिक स्थलों में शौचालय निर्माण के लिए गड्ढे खोदने का काम चला। इसका इतना प्रभाव पड़ा कि इन दिनों प्रदेश भर में लोग अपने घरों में शौचालय बनाते दिखे।

यद्यपि औपचारिक रूप से अभियान भले ही दो अक्टूबर तक चला हो लेकिन इस अभियान ने एक स्थाई जन-जाग्रति और जन मानस में स्वच्छता के प्रति एक चेतना का संचार किया। इसका नजारा विदिशा जिले के अंतर्गत ग्राम कागपुर में देखने को मिला। यह गाँव विदिशा और बासौदा के बीच सड़क मार्ग पर लगभग बीच में होगा। मैं अपनी यात्रा में चाय पीने के लिए रुका। उसी दुकान पर एक सज्जन ने भजिए खाकर अखबार का टुकड़ा वहीं पटक दिया। तभी वहीं पत्थर की बेंचनुमा बैठक पर बैठे सज्जन ने टोका और कागज उस कोने में रखे 'पीपे' में डाला दरअसल दुकानदार ने एक तेल का पीपे नुमा डब्बा वहां कचरे के लिए रखा था। फेंकने वाले ने अपना कागज उठाया उस डिब्बे में डाल दिया। बाद में इसी विषय पर चर्चा होने लगी। जो लोग बैठे थे, उन सबने सरकार के इस अभियान की चर्चा की, तारीफ की। लेकिन किसी ने यह जरूर कहा कि लोगों की समझ में आए तब तो सफाई हो। किसी ने इस बात का भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद किसी गाँव में जाकर शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदा और पूरा खोदा।

यह बातचीत, या किसी एक ग्राहक द्वारा दूसरे ग्राहक से कागज को कचरे के डिब्बे में डालने का कहना इस बात का संकेत है कि अभियान भले ही अधिकृत तौर पर पन्द्रह सितम्बर से दो अक्टूबर तक चला हो लेकिन लोगों में जो चेतना आ रही है यही चेतना मध्यप्रदेश को और उसके गांवों को साफ सुथरा बनायेगी। ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य आदमी, कोई सामान्य ग्रामीणजन साफ सफाई के महत्व को नहीं जानता। वह जानता है और यह भी मानता है कि बीमारियां गंदगी से आती हैं लेकिन उसमें एक चेतना का अभाव था, जाग्रति का अभाव था। इस अभियान से इसी चेतना का संचार हुआ है और जन सामान्य में जाग्रति भी आ रही है।

इस वर्ष का यह अभियान बहुत व्यापक और विभिन्न आयामों पर केन्द्रित था। यद्यपि प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सफाई अभियान की शुरुआत की लेकिन मुख्य कार्यक्रम रायसेन जिले के सांची विकासखंड के अंतर्गत ग्राम रतनपुर में आयोजित किया गया। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं कुदाल चलाकर शौचालय के लिए गड्ढा खोदा। सामान्य तौर पर जनप्रतिनिधि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन शिवराज जी ने केवल आरंभ करके ही अपनी कुदाल बंद नहीं की बल्कि वे लगातार दस मिनिट तक कुदाल ही चलाते रहे और उन्होंने स्वयं गड्ढे को गहरा किया। उनके इस परिश्रम की चर्चा सब जगह सुनी गई। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सागर जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत रहली के ग्राम हरदी में स्वयं न केवल गड्ढा खोदा अपितु स्वयं मिट्टी निकालकर उसे साफ किया और चौड़ा किया। जनप्रतिनिधियों की ऐसी दिलचस्पी ही अभियान की सार्थकता मानी जा सकती है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यह तीसरा अभियान था। जिसकी घोषणा

र हुआ है स्वच्छता सेवा अभियान से

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी उन्होंने न केवल भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया बल्कि इस महाप्रयास को जन भागीदारी से पूरा करने का आह्वान किया है। यह बात सही है कोई भी काम केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता सरकार केवल समन्वयक हो सकती है। अपने घर, अपना गाँव अपनी गली मोहल्ले को साफ रखने की चेतना पहले जन सामान्य में ही होना चाहिए। इसीलिए महात्मा गाँधी की जयंती को केन्द्र में रखकर स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना की गई। इस वर्ष इस अभियान की शुरुआत के समय ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 'स्वच्छता ही सेवा' संकल्पना की घोषणा की और अभियान की रूपरेखा को समस्त प्रतिनिधियों तथा संबंधित अधिकारियों को समझाया। वहीं अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया ने सभी कार्यपालन अधिकारियों तथा जिला पंचायत के सभी संबंधितों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। इतनी व्यापक और व्यवस्थित तैयारियों के कारण ही 15 सितम्बर को यह अभियान प्रदेश के सभी 51 जिलों एवं 313 विकास खंड मुख्यालयों पर एक साथ आरंभ हो सका और शाम 3.35 बजे सभी स्थानों पर एक साथ स्वच्छता की शपथ ली गई। इस अभियान के अंतर्गत 650 स्वच्छता रथों के माध्यम से 22816 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसे एक बड़ी उपलब्धि ही माना जायेगा कि प्रदेश के दो जिले, 397 ग्राम पंचायतें और 752 ग्राम खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए।

इस साल का यह अभियान अपेक्षाकृत अधिक व्यापक और तकनीकि के प्रयोग से भरा था फिल्मों का प्रसारण, स्वच्छता पर पंचायतों में परस्पर चर्चा और स्वच्छता रथ द्वारा केवल प्रचार करना नहीं था बल्कि उसके महत्व के बारे में भी जिज्ञासाओं को शांत करने का सिलसिला चला। अभियान की समूची अवधि में प्रतिदिन प्रभात फेरियां निकलीं, भजन मंडलियों ने सफाई पर केन्द्रित भजन और गीत सुनाए तो कला मंडलियों ने सफाई पर नुक्कड़ नाटक तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर जन-जाग्रति और चेतना के संचार का काम किया। इसके साथ-साथ सभी संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाली जनसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्कूलों के छात्र-छात्राएं भी लोगों को सफाई का महत्व समझाने निकले, खुले में शौच न करने की अपील करने तथा इस प्रकार की गंदगी कितनी हानिप्रद हो सकती है, यह समझाने निकले।

● रमेश शर्मा

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं)

स्वच्छता ही है सच्ची मनुष्यता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता अभियान को गति देकर इस तथ्य को रेखांकित किया है कि 'स्वच्छता ही मनुष्यता' है। स्वच्छता का संबंध हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्वास्थ्य से है। हम तो पूजा-अर्चना के पहले अपने देवी-देवताओं को भी स्नान करवाते हैं। मत्र है : स्नानम् ध्यानम् समर्पयामि...।

लोक स्वास्थ्य के बुनियादी उसूलों और व्यवहारों से समाज को जागृत करने के लिये "स्वच्छता ही सेवा है" के लोकमंगलकारी नारे के साथ स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया जो अब एक जन-आन्दोलन बनकर नगर-नगर और गाँव-गाँव में फैल चुका है। भारत सरकार के स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय ने इसके लिये सराहनीय पहल की और प्रदेश सरकार ने उसे अमली जामा पहनाया। प्रधानमंत्री जी ने 15 सितंबर से दो अक्टूबर तक जिस स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया उसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने मैदानी हालात में शत-प्रतिशत सफल बना दिया।

इसकी सफलता के लिये बाकायदा लक्ष्य निर्धारित किये गये। उन्हें पूरा करने के उपाय और तरीके निर्धारित किये गये। इसके परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश के एक चौथाई जिले खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) पा चुके हैं। "टायलेट एक प्रेमकथा" फिल्म का व्यापक प्रदर्शन किया गया जिसका अनुकूल प्रभाव हुआ। लगभग 20 लाख लोगों ने यह फिल्म देखी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने पंचायत स्तर पर इस अभियान में व्यक्तिगत रुचि लेकर इस अभियान की सफलता सुनिश्चित की। नगरों और ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कराने (ओडीएफ) में स्थानीय स्वशासन निकायों की निर्णायक भूमिका रही। शौचालयविहीन घरों में श्रमदान करके ट्विन-पिट तकनीक से शौचालय के गड्ढे खोदे गये। रायसेन जिले में रतनपुर ग्राम की 37 वर्षीया विधवा अनीता जाटव तो यह देखकर गद्-गद् हो गईं कि स्वयं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान उनके घर में शौचालय का गड्ढा खोद रहे थे।

स्वच्छता रथों के माध्यम से गाँव-गाँव में प्रचार किया गया। प्रदेश के कुल 51 जिलों की 22816 पंचायतों में 650 स्वच्छता रथों के माध्यम से जनजागृति हेतु सघन प्रचार किया गया। मुख्यमंत्री जी ने इन्दौर में स्वयं हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था। सत्रह सितंबर से दो अक्टूबर तक लगातार स्वच्छता रथ-यात्रा से स्वच्छता संदेश का सफल और विस्तृत प्रचार किया गया। इसकी यात्रा और समय चक्र इस प्रकार बनाया गया कि यह रथ प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कम से कम तीन घंटे तो अवश्य प्रचार करें। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सड़सठवे जन्मदिवस पर स्वच्छता रथों का शुभ प्रयाण किया।

अल्पवर्षा के संदर्भ तथा स्वच्छता के लिये जल के महत्व के मद्देनजर पानी रोको अभियान भी मैदानी स्तर पर लागू किया गया। इसके लिये स्थानीय नदी-नालों जैसे जलस्रोतों में श्रमदान के जरिये बोरीबंधान करके जल रोको अभियान को अमली जामा पहनाया गया।

इन सभी अभियानों से विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं को विशेष रूप से जोड़ा गया। लगभग सभी जिलों के स्कूलों में विद्यार्थियों को लेकर स्वच्छता विषयक निबंध

प्रतियोगितायें आयोजित की गईं, जिनमें लाखों विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों के 'बाल कमान्डो' गठित किये गये जो बढ़िया काम कर रहे हैं। इससे स्वच्छता का संदेश घर-घर पहुंच रहा है।

हर्ष का विषय है कि प्रदेश में एक अद्‌भुत स्वच्छता संस्कृति और विलक्षण स्वच्छता आर्थिकी का विकास हो रहा है। जाने माने अभिनेता अक्षयकुमार ने इससे प्रभावित होकर अप्रैल 2017 में स्वयं गड्ढे खोदकर मिट्टी डाली ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को ओडीएफ बनाने के लिये ट्विन लीच पिट तकनीक को लोकप्रिय बनाकर उसका विस्तार किया जाये। प्रदेश में ऐसे दो लाख से अधिक पिट (गड्ढे) बनाये जा चुके हैं। यह काम अभी भी जारी है। अधिकांश स्वच्छता योजनाओं को मनरेगा से भी जोड़ दिया गया है। समग्र स्वच्छता के क्षेत्र में एक मैदानी नेतृत्व का स्वयमेव उदय होना प्रसन्नता का विषय है। ऐसे अनेक सक्रिय कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान से सम्मानित किया गया है।

सितंबर-अक्टूबर मास हमारे देश की दो महान विभूतियों महात्मा गाँधी और पं. दीनदयाल उपाध्याय का पुण्य स्मरण कराते हैं। इन दोनों महामनीषियों ने अंदर-बाहर की स्वच्छता यानी तन-मन की स्वच्छता पर विशेष बल दिया था। अतः महात्मा गाँधी की जन्मतिथि दो अक्टूबर को स्थानीय नेतृत्व को विशेष आयोजनों में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 1269 सरपंचों, 939 बाल-मंत्रिमंडलों, 973 भजन मंडलियों, 3807 सफाई कर्मियों और 3130 किशोरी-छात्राओं को मुख्यमंत्री सम्मान से नवाज़ा गया। इस समूचे कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार, कार्यान्विति और सफलता के आकलन के बाकायदा मानक और मानदंड बनाकर उसकी वस्तुपरक मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी स्वच्छता योजनाओं से माननीय मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों आदि को सक्रिय रूप से जोड़ा गया है।

● **घनश्याम सक्सेना**
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

स्वच्छता अभियान के उद्देश्य

- स्वच्छ भारत अभियान को जन-आन्दोलन बनाकर इस पहल को जन-जन तक पहुंचाना और सुदृढ़ बनाना।
- स्वच्छता दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाकर ट्विन लीच पिट तकनीकी को लोकप्रिय बनाना।
- स्वच्छ भारत अभियान की मैदानी सफलता सुनिश्चित करने वाले स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहन एवं मान्यता।

अभियान के घटक

- घरों, संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान के माध्यम से शौचालय के लिए गड्ढे खोदना तथा स्वच्छ जल व्यवस्था।
- ग्रामों, शालाओं आदि में स्वच्छता विषयक शपथग्रहण समारोह आयोजित करके पर्यावरण स्वच्छता सुनिश्चित करना।
- ग्राम और ब्लाक स्तर पर सर्व संबंधितों में क्षमता निर्माण ताकि समग्र स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो सके।
- उचित और उपयुक्त संप्रेषण द्वारा व्यवहार परिवर्तन ताकि समाज में योजना के प्रति अनुकूल वातावरण बन सके।
- सभी प्रचार माध्यमों का व्यापक उपयोग।

परिणाम : उपलब्धियाँ

- श्रमदान से 2,16,074 ट्विन पिटों का निर्माण।
- प्रदेश की 22,816 ग्राम पंचायतों में 650 स्वच्छता रथों के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान के संदेश का प्रचार-प्रसार।
- एक लाख से अधिक परिवारों में सम्पर्क और स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार।
- दो जिले, 397 ग्राम पंचायतें और 752 ग्राम खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित।
- ओडीएफ हो चुके ग्राम पंचायत क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- जल-मल निकास हेतु पक्की नालियों का निर्माण।

जन-जन जुड़ा स्वच्छता ही से

स्वच्छ भारत मिशन की तीसरी वर्षगाँठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2017 तक व्यापक जन भागीदारी द्वारा राष्ट्रव्यापी 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान आयोजित करने का आह्वान किया। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संभाग आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला पंचायत के अध्यक्षों को विभिन्न गतिविधियों के समय-चक्र से अवगत कराते हुए सभी को इस अवधि में स्वच्छता के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने तथा आम जन और जन प्रतिनिधियों को कार्यक्रम में भागीदार बनाने के निर्देश दिये। केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए 15 सितंबर 2017 से स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। यह एक देशव्यापी अभियान था जिसे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कानपुर देहात के ईश्वरीगंज गाँव से शुरू किया गया। जिससे देश भर में एक साथ स्वच्छता ही सेवा की शुरुआत हुई। इस राष्ट्रव्यापी अभियान को मध्यप्रदेश में स्वच्छता रथ को हरी झंडी देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया। प्रत्येक जिले में कार्ययोजना की रूप-रेखा अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत हुई।

स्वच्छता ही सेवा की विशेषता

इस अभियान में सभी क्षेत्रों से लोगों को जोड़ा गया। लोगों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े जमीनी कार्यकर्ताओं, बच्चों और समुदाय के सभी लोगों ने इस अभियान को जन आन्दोलन का रूप दिया।

जागरुकता से ही आएगा बदलाव

जागरुकता से ही बदलाव आएगा। इस उद्देश्य से लोगों के बीच स्वच्छता पर चर्चा शुरू की गई जिसके लिए अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में "स्वच्छता रथ" को हरी झंडी दिखा कर किया। सभी 51 जिलों तथा 313 ब्लॉक मुख्यालयों पर अभियान का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया जिसमें सभी क्षेत्रों में माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में अपरान्ह 3.35 बजे स्वच्छता की शपथ ली गई।

मुख्यमंत्री द्वारा किये श्रमदान ने लोगों को प्रेरित किया जिसके कारण एक दिन में 2 लाख शौचालयों के गड्ढे पूरे प्रदेश में खोदे गए जिससे लोगों के सहयोग एवं स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों के जुड़ाव को समझा जा सकता है।

"सेवा दिवस" 17 सितम्बर के दिन पूरे प्रदेश में ट्विन पिट की तकनीक के शौचालय निर्माण हेतु श्रमदान द्वारा गड्ढे खोद कर "सेवा दिवस" के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री जी ने रायसेन एवं छतरपुर जिले में, श्री गोपाल भार्गव, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा सागर जिले में श्रमदान कर शौचालय का गड्ढा खोदा गया एवं जल रोको गतिविधि की गई। इस दिन प्रदेश भर में 2,16,074 गड्ढे खोदे गये। अभियान अवधि में 1 लाख शौचालय निर्मित हुए। मनोरंजन के माध्यम से भी वातावरण निर्माण किया गया जैसे कि इसी दिन प्रातः 11.30 बजे सभी 22,816 ग्राम पंचायतों के कार्यालय में दूरदर्शन द्वारा प्रसारित "टॉयलेट एक प्रेम कथा" फिल्म का प्रसारण किया गया। जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक स्थलों पर फिल्म स्क्रीन की सुविधा प्रदान कर फिल्म का प्रदर्शन किया गया जिसे लोगों ने पसंद भी किया और खुले में शौच की गंभीरता को समझा। रायसेन की श्रीमती कुन्ती देवी का कहना है कि "ऐसी फिल्मों से समाज में प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा।"

स्वच्छता ही सेवा तथा जल रोको अभियान के तहत 18 से 24 सितम्बर तक

ा और जल रोको अभियान में

जनभागीदारी से प्रत्येक ग्राम में सफाई अभियान चलाया गया तथा शासकीय

दो अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। इस दिन सभी जिलों में स्वच्छता दिवस मनाया गया। विशेष रूप से होशंगाबाद जिले में मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जिले के पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त होने की घोषणा की गई। स्वच्छता समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। प्रत्येक जनपद पंचायत में ओ.डी.एफ. करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बालक, बालिकाओं, भजन मंडलियों, सफाई कर्मियों तथा सरपंचों आदि को आमंत्रित किया गया। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में इसी प्रकार का आयोजन कर इस राष्ट्रव्यापी अभियान को मनाया गया। जिससे राज्य के स्वच्छता कार्यक्रम को और गति मिली। उम्मीद है आने वाले कुछ समय में ही इसी तरह के जन-सहयोग से मध्यप्रदेश पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त जो जायेगा।

● **साबिर इकबाल**
(राज्य सलाहकार, स्वच्छ भारत मिशन)

होशंगाबाद जिला खुले

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दो अक्टूबर को होशंगाबाद में आयोजित समारोह में होशंगाबाद जिले के खुले में शौच से पूर्णतः मुक्त (ओ.डी.एफ.) होने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में कहा कि जहां स्वच्छता का वास होता है, वहां ईश्वर का वास होता है। स्वच्छता के दूत महात्मा गाँधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि गाँधी जी स्वयं स्वच्छता के हिमायती थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वच्छता के प्रति देशवासियों का नजरिया बदल दिया है। पहले लोग सड़कों पर, दफ्तरों में कचरा फैलाया करते थे, किन्तु अब लोगों का नजरिया बदल गया है। अब लोग कचरा डस्टबिन में डालते हैं। मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद की सभी ग्राम पंचायतों के खुले में शौच मुक्त होने की सराहना करते हुए कहा कि यह सब यहां की जनता, जन-प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और पंचायत कर्मियों के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद जिले की 424 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। इन ग्राम पंचायतों में 883 गाँव शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा इन ग्राम पंचायतों में 57 हजार 855 शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शौचालय तो बन गये हैं, लोग उनका उपयोग भी करें। शौचालय का उपयोग करने की आदत डालें। शौचालय में भी साफ-सफाई रखें और अपने हाथ साबुन से अवश्य धोएं। हमें अब अपनी मानसिकता बदलनी होगी। इससे हमारे घर की मर्यादा भी बनी रहेगी। मैंने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान प्रण किया था कि माँ नर्मदा को स्वच्छ बनाएंगे। इसके लिये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 155 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से सीवेज के पानी को शुद्ध कर खेती में उपयोग किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा की सीवेज के पानी की एक बूंद भी माँ नर्मदा में न मिले।

श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर जिला देश का नम्बर एक जिला घोषित हुआ है। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष श्री अखिलेश खंडेलवाल को निर्देश दिये कि स्वच्छता के मामले में होशंगाबाद जिले को देश का अव्वल जिला बनायें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बनाये गये 2 लाख

में शौच से पूर्णतः मुक्त

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वच्छता के प्रति देशवासियों का नजरिया बदल दिया है। पहले लोग सड़कों पर, दफ्तरों में कचरा फैलाया करते थे, किन्तु अब लोगों का नजरिया बदल गया है। अब लोग कचरा डस्टबिन में डालते हैं। मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद की सभी ग्राम पंचायतों के खुले में शौच मुक्त होने की सराहना करते हुए कहा कि यह सब यहां की जनता, जन-प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और पंचायत कर्मियों के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। होशंगाबाद जिले की 424 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। इन ग्राम पंचायतों में 883 गाँव शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा इन ग्राम पंचायतों में 57 हजार 855 शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

प्रधानमंत्री आवासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अथक प्रयासों से संभव हो सका है। आने वाले 4-5 वर्षों में हर गरीब के पास पक्की छत होगी। उन्होंने कहा कि रेत खनन की अनुमति अब ग्राम पंचायतें देंगी।

स्वच्छता समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-स्वच्छता दूत बनने पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री कुशल पटेल, कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.सी. शर्मा एवं जिला समन्वयक की पूरी टीम को मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर्स को पुरस्कार प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सरपंचों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने गाँव-गाँव स्वच्छता का अलख जगाने वाली बालटोली मुहांसा को स्वच्छता का प्रमाण पत्र प्रदान किया। किशोरी स्वच्छता पुरस्कार के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने प्रियंका यदुवंशी को तथा स्वच्छता का संदेश घर-घर पहुँचाने वाली भजन मंडली झंकर पगढाल को तथा किशोरी टोली की बालिकाओं को भी पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने प्रेरक मंडल

प्रणेताओं को भी सम्मानित किया।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा ने आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में देश का अव्वल राज्य बनेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में सभी तहसील शत-प्रतिशत सिंचाई की स्थिति में हैं। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। अगले वर्ष 52 हजार गाँव पुल-पुलियों से जुड़ जायेंगे। प्रधानमंत्री आवास बनाने में मध्यप्रदेश देश का नंबर वन राज्य बन गया है। श्री भार्गव ने कहा कि आने वाले समय में समूचा प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कुशल पटेल ने अतिथियों का स्वागत किया।

कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण, उद्यानिकी एवं वन राज्यमंत्री श्री सूर्य प्रकाश मीणा, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह, विधायक श्री सरताज सिंह, श्री विजयपाल सिंह, श्री ठाकुरदास नागवंशी, पूर्व राजस्व मंत्री श्री मधुकरराव हर्णे, राज्य अंत्योदय समिति के सदस्य श्री हरिशंकर जायसवाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया भी उपस्थित थे।

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए उचित आधुनिक एवं वैज्ञानिक व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों को 26 क्लस्टर में बाँट कर जन-निजी भागीदारी (पी.पी.पी. मोड) से एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें 6 क्लस्टर आधारित परियोजनाएँ कचरे से बिजली (waste to energy) तथा 20 परियोजनाएँ कचरे से खाद बनाने (waste to compost) का काम करेंगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिन 26 क्लस्टर्स में इस परियोजना को लागू किया गया है उनमें भोपाल, रीवा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर तथा रतलाम में कचरे से बिजली का उत्पादन किया जायेगा।

इस परियोजना को जबलपुर में सफलता से क्रियान्वित कर 10 मेगावॉट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। रुपये 1555 करोड़ की लागत की सभी 6 परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद प्रदेश के 78 निकायों में प्रतिदिन के लगभग 3500 टन कचरे से 72 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। इन क्लस्टर के तहत भोपाल क्षेत्र के 8 नगरीय निकाय, रीवा के 28, ग्वालियर के 16, जबलपुर 16 तथा रतलाम क्षेत्र के 17 नगरीय निकाय शामिल हैं।

कचरे से खाद बनाने वाली 20 परियोजनाओं में कटनी, सागर, होशंगाबाद, उज्जैन, देवास, खंडवा, भिण्ड, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, बैतूल, दमोह, शहडोल, बड़वानी, नीमच, बालाघाट, विदिशा, गुना, सिंगरौली, शिवपुरी तथा शाजापुर शामिल हैं। रुपये 1326 करोड़ की लागत से स्थापित होने वाली इन परियोजनाओं से 300 निकायों के लगभग 3000 टन कूड़े से 450 टन जैविक खाद का उत्पादन किया जायेगा। इसमें कटनी के 5 नगरीय निकाय, सागर के 11, होशंगाबाद के 14, देवास के 24, खंडवा के 10, भिंड के 14, छिन्दवाड़ा के 20, छतरपुर के 33, बैतूल के 8, दमोह के 7 और शहडोल क्षेत्र के 16 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है।

चिन्हित 26 क्लस्टर्स में से 9 क्लस्टर्स पर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष 17 क्लस्टर्स की टेंडर व मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है।

साझा प्रयासों से शत-प्रतिशत
स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करेंगे

स्वच्छता के संदेश के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। देश में स्वच्छता का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। पहले जहां स्वच्छता का प्रतिशत मात्र 39 था, जो अब बढ़कर 67 हो गया है। सरकार और समाज के साझा प्रयासों से इसे शत-प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य है। "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के शुभारंभ अवसर पर केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने घर-घर स्वच्छता का संदेश पहुँचाने के लिये स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस पर ग्वालियर में "स्वच्छता ही सेवा" कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह भी उपस्थित थीं। इस अवसर पर लोगों ने स्वच्छता की शपथ भी ली।

श्री तोमर ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता के संदेश के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। देश में स्वच्छता का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। पहले जहां स्वच्छता का प्रतिशत मात्र 39 था, जो अब बढ़कर 67 हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के साझा प्रयासों से इसे शत-प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य है। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर एवं नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने इस अवसर पर घर-घर स्वच्छता का संदेश पहुँचाने के लिये स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्रीद्वय ने इस मौके पर सामूहिक पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे।

कार्यक्रम में महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर, साडा अध्यक्ष श्री राकेश जादौन व नगर निगम सभापति श्री राकेश माहौर, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती प्रमिला वाजपेयी, पूर्व मंत्री श्री ध्यानेन्द्र सिंह, श्री शैलेन्द्र बरूआ एवं श्री देवेश शर्मा ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। शहर भर से स्वच्छता रैली के रूप में आये युवाओं व महिलाओं ने भी स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

स्वच्छता अभियान से देश को मिलेगी गंदगी से मुक्ति

वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया 17 सितम्बर को भोपाल के पंचशील नगर में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान में शामिल हुए। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से देश के साथ मध्यप्रदेश को भी गंदगी से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से अभियान में जागरुकता के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह किया। वित्त मंत्री ने कमजोर वर्ग के दिनेश चावरिया के मकान में ट्विन-पिट खोदने की शुरुआत की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से देश के साथ मध्यप्रदेश को भी गंदगी से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। वित्तमंत्री श्री जयंत मलैया ने "स्वच्छता ही सेवा" अभियान में लोगों को जागरुकता के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि घर की सफाई के साथ-साथ मोहल्ले की सफाई की तरफ भी नागरिकों को ध्यान देना होगा। समाज में महिलाओं की भागीदारी की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी अच्छे काम को महिलाओं के सामूहिक प्रयास अच्छी दिशा दे सकते हैं।

वित्त मंत्री श्री मलैया ने कहा कि घर में शौचालय का निर्माण गंदगी से मुक्ति के लिये बेहद जरूरी है। सौ में से 75 बीमारियों की वजह गंदगी होती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान मध्यप्रदेश में जन-आंदोलन बन चुका है। घर की सफाई के साथ-साथ मोहल्ले की सफाई की तरफ भी नागरिकों को ध्यान देना होगा। समाज में महिलाओं की भागीदारी की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी अच्छे काम को महिलाओं के सामूहिक प्रयास अच्छी दिशा दे सकते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि शौचालय निर्माण के लिये प्रत्येक हितग्राही को 13 हजार 600 रुपये दिए जा रहे हैं। जन-प्रतिनिधियों का दायित्व है कि वे इस राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करें।

पंचशील नगर में इस अभियान के तहत 400 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। वार्ड में 200 शौचालयों का निर्माण अक्टूबर माह के अंत तक कर दिया जाएगा। पंचशील नगर में नागरिकों के घरों में नर्मदा जल के 5000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वार्ड में 2 वर्ष में 50 लाख की लागत से नागरिकों की सुविधा के लिए सी.सी. नाली निर्माण और 70 लाख की लागत से सी.सी. रोड का निर्माण किया गया है। सांसद निधि से 40 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण भी करवाया गया है। सार्वजनिक पार्क के निर्माण पर 10 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। वार्ड में विकास के करीब 3 करोड़ रुपये के काम करवाए जा चुके हैं।

जनता ने दिया स्वच्छता अभियान को समर्थन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान से पूरा देश जुड़ गया है। देश में स्वच्छता का महत्व समझकर लोग खुद स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छता जैसे सकारात्मक और सार्थक विषय को भारत के साथ ही अन्य देश भी स्वीकार कर, समर्थन दे रहे हैं।

जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस पर 17 सितम्बर को दतिया नगर की अनुसूचित जाति बहुल बस्ती में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने 10 लाख रुपये लागत के स्वच्छ शौचालय के निर्माण की आधारशिला रखी। डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी तो कुछ लोगों ने उनके झाड़ू उठाने पर सवाल खड़े कर दिए थे। आज देश में स्वच्छता का महत्व समझकर लोग खुद स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छता जैसे सकारात्मक और सार्थक विषय को भारत के साथ ही अन्य देश भी स्वीकार कर समर्थन दे रहे हैं।

जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने दतिया में एक कार्यक्रम में जिले के 16 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। राजघाट कॉलोनी में हुए समारोह में जनसंपर्क मंत्री ने कुश्ती, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, कबड्डी, ताइकान्डो के खिलाड़ियों को राशि प्रदान करते हुए शुभकामनाएं दीं। डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया निवासी श्री श्रीनाथ पटेरिया, श्री रघुवीर अहिरवार और श्री भूपेन्द्र सिंह सिरोनिया को शासकीस सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश प्रदान किये। जनसंपर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने दतिया में नवरात्रि पर्व के दौरान होने वाले कार्यक्रमों, रामलीला, दशहरा चल समारोह और रावण दहन के संबंध में विभिन्न समितियों की बैठकों में समिति सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया।

● **अशोक मनवानी**
(उप संचालक, जनसंपर्क)

प्रदेश में एक लाखव

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 सितम्बर को प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही और प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही को सम्मानित किया। उन्होंने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि ये अन्य हितग्राहियों के लिये प्रेरणा-स्रोत हैं। श्री चौहान ने गरीबों के हित की यह योजना शुरू करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। योजना में आवास बनाने में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के एक लाखवें हितग्राही दमोह जिले के ग्राम बुडेला निवासी श्री बल्लू धनीराम यादव तथा देश में सबसे सुंदर आवास बनाने वाले हितग्राही उमरिया जिले के ग्राम सलैया के श्री रामकृष्ण तिवारी को 11-11 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने दोनों को उनके कार्य की सराहना करते हुए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इस बात की मिसाल है कि हितग्राही की मेहनत से बेहतर मकान बनाये जा सकते हैं।

श्री चौहान ने कहा कि सरकार के गरीब कल्याण एजेंडे का सबसे प्रमुख बिन्दु गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की महती भूमिका है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना में देश में गरीबों के सर्वाधिक मकान मध्यप्रदेश में बनाये गये हैं। अक्टूबर अंत तक 3 लाख आवास तथा इस वर्ष के अंत तक 7 लाख आवास पूरे करने का लक्ष्य है। प्रदेश में अभी तक एक लाख 15 हजार 689 आवास पूरे किये जा चुके हैं। योजना में कुल 7 लाख 62 हजार 328 आवास स्वीकृत किये गये हैं। योजना में हितग्राही को एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि के अलावा शौचालय एवं मनरेगा के तहत मजदूरी भी उपलब्ध करवायी जाती है। दोनों हितग्राहियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पक्के मकान बन जाने से उनके परिवार को बड़ी सहूलियत हो गई है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.एस. जुलानिया और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना में प्रदेश अग्रणी

मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी है। प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में योजना में करीब 2 लाख 13 हजार आवासों का निर्माण कर हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। कुल 5 लाख 44 हजार 849 आवास निर्माणाधीन हैं, जो इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिये जायेंगे। लक्ष्य 7 लाख 57 हजार 593 आवास निर्माण का है।

प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजना में संभागवार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इसके अनुसार भोपाल संभाग के अंतर्गत भोपाल जिले में 5989 के लक्ष्य के विरुद्ध 2668 आवास का निर्माण, रायसेन में 21 हजार 308 के लक्ष्य के विरुद्ध 4700 आवास, विदिशा में 20 हजार 981 के लक्ष्य के विरुद्ध में 4574 आवास, सीहोर में 12 हजार 747 के लक्ष्य के विरुद्ध में 5634 आवास और राजगढ़ जिले में 25 हजार 011 के लक्ष्य के विरुद्ध 11 हजार 140 आवासों का निर्माण किया गया। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में 12 हजार 201 के लक्ष्य के विरुद्ध 3916 आवासों का निर्माण, बैतूल में 13 हजार 738 के लक्ष्य के विरुद्ध 3537 आवास और हरदा जिले में 5187 के लक्ष्य

ं आवास हितग्राही सम्मानित

के विरुद्ध 1661 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया। इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर जिले में 4071 के लक्ष्य के विरुद्ध 2360 आवासों का निर्माण, धार में 23 हजार 565 के लक्ष्य के विरुद्ध 6445 आवास, अलीराजपुर में 14 हजार 075 के लक्ष्य के विरुद्ध 2534 आवास, झाबुआ में 17 हजार 716 के लक्ष्य के विरुद्ध 2907 आवास, खण्डवा में 10 हजार 878 के लक्ष्य के विरुद्ध 2699 आवास, बुरहानपुर में 6929 के लक्ष्य के विरुद्ध 2729 आवास, खरगोन में 21 हजार 287 के लक्ष्य के विरुद्ध 6831 आवास और बड़वानी जिले में 15 हजार 737 के लक्ष्य के विरुद्ध 3292 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया।

उज्जैन संभाग के अंतर्गत उज्जैन जिले में 9930 के लक्ष्य के विरुद्ध में 6902 आवासों का निर्माण, शाजापुर में 5834 के लक्ष्य के विरुद्ध में 2610 आवास, आगर-मालवा में 5974 के लक्ष्य के विरुद्ध 3650 आवास, रतलाम में 15 हजार 901 के लक्ष्य के के लक्ष्य के विरुद्ध 6763 आवास, मण्डला में 21 हजार 735 के लक्ष्य के विरुद्ध 4437 आवास और बालाघाट जिले में 17 हजार 077 के लक्ष्य के विरुद्ध 5627 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया।

रीवा संभाग के अंतर्गत रीवा जिले में 25 हजार 172 के लक्ष्य के विरुद्ध में 3350 आवास का निर्माण, सिंगरौली में 13 हजार 770 के लक्ष्य के विरुद्ध 716 आवास, सीधी में 12 हजार 612 के लक्ष्य के विरुद्ध 1314 आवास और सतना जिले में 23 हजार 967 के लक्ष्य के विरुद्ध 4850 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया। शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल जिले में 24 हजार 403 के लक्ष्य के विरुद्ध में 5408 आवास का निर्माण, अनूपपुर में 13 हजार 001 के लक्ष्य के विरुद्ध 3173 आवास और उमरिया जिले में 14 हजार 549 के लक्ष्य के विरुद्ध में 2425 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया।

● **के.के. जोशी**
सहायक संचालक, जनसंपर्क

सतवंती के बनाये मॉडल को प्रधानमंत्री ने सराहा

मनरेगा की रेशम योजना से आय हो गई चौगुनी

नई दिल्ली स्थित पूसा के मैला मैदान में 11 अक्टूबर को नानाजी देशमुख की जन्मशती समारोह में आयोजित प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की लाभार्थी सतवंती बाई द्वारा मनरेगा की रेशम उपयोजना से हुई सफलता का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया। इसे देखकर श्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल मॉडल की सराहना की, बल्कि उन्होंने रेशम उपयोजना की मदद से सतवंती की मेहनत और उसकी सफलता का राज भी जाना। सतवंती ने बताया कि, रेशम की खेती से उसकी आय चौगुनी हो गई और उसके परिवार के अच्छे दिन भी आ गए हैं। प्रधानमंत्री के सामने मॉडल का प्रजेंटेशन देते हुए बालाघाट जिले के बुदबुदा गाँव की सतवंती ने बताया कि वे पहले परंपरागत खेती में धान, ज्वार आदि की फसल उगाती थीं, जिससे सालाना 30 से 35 हजार रुपये की आमदनी हो पाती थी। जिससे वह घर की जरूरतों को मुश्किल से पूरा कर पाती थीं। अब दो एकड़ जमीन में वह पहले से चौगुना मुनाफा कमा रही हैं। एक साल में चार बार रेशम का उत्पादन कर एक से सवा लाख रुपये सालाना कमा पा रही हैं। तंगहाली भरे जीवन से छुटकारा पाकर सफलता के पायदान पर पहुंची सतवंती ने प्रधानमंत्री को बताया कि रेशम की खेती से उसके अच्छे दिन आए हैं। इस आमदनी की बदौलत ही घर की सारी जरूरतें पूरी कर पाते हैं और दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया है जिसकी 35 हजार रुपये सालाना फीस भी जमा करते हैं, अब बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा-लिखा पा रहे हैं। सतवंती के मॉडल अवलोकन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ केन्द्रीय पंचायत व ग्रामीण विकास, खनिज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायती राज विकास मंत्री श्री रामकृपाल यादव, ग्रामीण विकास सचिव श्री अमरजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव श्रीमती अपराजिता सारंगी भी मौजूद थीं।

नई दिल्ली स्थित पूसा के मैला मैदान में 11 अक्टूबर को नानाजी देशमुख की जन्मशती समारोह में आयोजित प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की लाभार्थी सतवंती बाई द्वारा मनरेगा की रेशम उपयोजना से मिली सफलता का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया। इसे देखकर प्रधानमंत्री ने न केवल मॉडल की सराहना की, बल्कि उन्होंने रेशम उपयोजना की मदद से सतवंती की मेहनत और उसकी सफलता का राज भी जाना। सतवंती ने बताया कि वह पहले परंपरागत खेती में धान, ज्वार आदि की फसल उगाती थीं, जिससे सालाना 30 से 35 हजार रुपये की आमदनी हो पाती थी। जिससे वह घर की जरूरतों को मुश्किल से पूरा कर पाती थीं। अब दो एकड़ जमीन में वह पहले से चौगुना मुनाफा कमा रही हैं।

सतवंती ने नई दिल्ली के पूसा मैदान में आयोजित प्रदर्शनी में रेशम उपयोजना की सफलता का मॉडल प्रस्तुत कर मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। प्रदर्शनी में सतवंती ने देश के कई राज्यों से आए प्रतिनिधियों को अपनी सफलता की दास्तान सुनाई। सतवंती का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उसे जो प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है, वह उसके लिए बहुत गौरव की बात है।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश से लगभग एक हजार प्रतिभागी एस.आर.एल.एम., प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के लाभार्थी एवं ग्राम पंचायतों के सरपंच आदि शामिल हुए थे।

● **प्रीति नीखरा**
(लेखिका स्तंभकार हैं)

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने "स्वच्छता ही सेवा" अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री निवास से स्वच्छता रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के ग्राम रतनपुर में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान कार्यक्रम में हरी झण्डी दिखाकर स्वच्छता रथ को रवाना किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव सागर जिले में "स्वच्छता ही सेवा" कार्यक्रम में भाग लेने जाते हुए।

जिला पंचायत मण्डला द्वारा आयोजित "स्वच्छता ही सेवा" कार्यक्रम में भाग लेते प्रतिनिधि।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत कनेरी में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान के तहत श्रमदान किया।

केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने ग्वालियर में हरी झण्डी दिखाकर "स्वच्छता ही सेवा" अभियान का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदकर श्रमदान किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले के खुले में शौच से पूर्ण मुक्त होने पर किशोरी टोली और बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में सेवा दिवस पर स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया।

"स्वच्छता ही सेवा" अभियान में शामिल बच्चे स्वच्छता का संकल्प लेते हुए।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में सेवा दिवस पर "स्वच्छता ही सेवा" कार्यक्रम को संबोधित किया।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री राधेश्याम जुलानिया ने "स्वच्छता ही सेवा" कार्यक्रम में शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदकर श्रमदान किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले के सरपंचों को स्वच्छ ग्राम पंचायत पुरस्कार वितरित किये।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने सागर में आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा' और 'जल रोको अभियान' को संबोधित किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 'स्वच्छता ही सेवा' और 'जल रोको अभियान' के तहत बोरी बंधान किया।

सागर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रोहित सिंह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 'स्वच्छता ही सेवा' और 'जल रोको अभियान' में बोरी बंधान किया।

मनरेगा की रेशम योजना से
लखपति बनी सतवंती

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मनरेगा गरीब किसानों के जीवन में खुशहाली ला रही है। मनरेगा की विभिन्न योजनाओं का फायदा उठाकर ग्रामीणों को स्थायी आजीविका के संसाधन मुहैया हो रहे हैं। अतिरिक्त आमदनी से उनके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा व उन्नत जीवन अब उनके लिए दूर की कौड़ी नहीं है।

ऐसी ही एक हितग्राही है, मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत बुदबुदा की सतवंती बाई। जिन्होंने मनरेगा की रेशम योजना का भरपूर फायदा लिया है। अब सतवंती को सालाना एक लाख से अधिक की आमदनी कोकून बेचकर होने लगी है। इस आमदनी ने उनके परिवार में खुशहाली ला दी है। अब उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। घर में आधुनिक जरूरत के सभी संसाधन भी सतवंती के पास हैं।

ग्राम बुदबुदा की सतवंती के पास तीन एकड़ जमीन थी जिसमें वे मात्र परम्परागत फसल लेती थीं, जिससे सालाना 30 से 35 हजार रुपये की आमदनी ही हो पाती थी। जब उन्हें मनरेगा की रेशम उपयोजना की जानकारी मिली तो उन्होंने ग्राम पंचायत में रेशम के कीट पालन का लाभ लेने के लिए संपर्क किया। वर्ष 2014-15 में मनरेगा से दो लाख छः हजार तथा रेशम विभाग से दो लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। रेशम विभाग द्वारा कीट पालन के लिए रेयरिंग हाउस बनाया गया तथा मनरेगा से शहतूत प्रजाति के 2 एकड़ में दस हजार पौधे लगाये गये। पौधे लगाने व रखरखाव का काम भी सतवंती व उनके परिवार ने किया जिसकी मजदूरी भी हासिल हुई और इन पौधों की बदौलत कोकून का उत्पादन होने से सालाना तकरीबन एक लाख रुपये से अधिक की आमदनी होने लगी।

बालाघाट जिले के ग्राम बुदबुदा की सतवंती के पास तीन एकड़ जमीन थी जिसमें वे परम्परागत फसल ही लेती थीं, जिससे सालाना 30 से 35 हजार रुपये की आमदनी हो पाती थी। जब उन्हें मनरेगा की रेशम उपयोजना की जानकारी मिली तो उन्होंने ग्राम पंचायत में रेशम के कीट पालन का लाभ लेने के लिए संपर्क किया। वर्ष 2014-15 में मनरेगा से दो लाख छः हजार तथा रेशम विभाग से दो लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। रेशम विभाग द्वारा कीट पालन के लिए रेयरिंग हाउस बनाया गया तथा मनरेगा से शहतूत प्रजाति के 2 एकड़ में दस हजार पौधे लगाये गये। पौधे लगाने व रखरखाव का काम भी सतवंती व उनके परिवार ने किया जिसकी मजदूरी भी हासिल हुई, और इन पौधों की बदौलत कोकून का उत्पादन होने से सालाना तकरीबन एक लाख रुपये से अधिक की आमदनी होने लगी।

सतवंती ने बताया कि वे पहले परंपरागत खेती में धान, ज्वार आदि की फसल उगाती थीं, जिससे सालाना 30 से 35 हजार रुपये की आमदनी हो पाती थी। पर अब मनरेगा की रेशम उपयोजना से एक लाख रुपये से अधिक आमदनी हो जाती है।

एक बार में एक क्विंटल कोकून 300 रुपये के हिसाब से बिकता है इस तरह साल में चार बार कोकून का उत्पादन होता है। इस आमदनी की बदौलत ही घर की सारी जरूरतें पूरी कर पाते हैं और दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया है जिसकी 35 हजार रुपये सालाना फीस भी जमा करते हैं, अब बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा-लिखा पा रहे हैं।

● **अभिषेक सिंह**
(लेखक स्तंभकार हैं)

पूर्ण स्वच्छ पेयजल की पहली अनूठी पंचायत बनी कोदरिया

ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने लगाए वाटर ए.टी.एम.

इंदौर जिले की कोदरिया की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी ने पेयजल को लेकर अनूठा नवाचार किया है। इसके तहत ग्रामीणों को दस रुपये में 20 लीटर आर.ओ. वाटर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला नवाचार है। मार्च 2015 में सरपंच चुनी गईं श्रीमती अनुराधा जोशी ने ढाई वर्षों में अपनी पंचायत का कायाकल्प कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने पंचायत के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया। स्व-करारोपण और बकाया संपत्ति कर आदि से पहले जहां पंचायत की आय मात्र साढ़े चार सौ रुपये थी, उसे बढ़ाकर 20 लाख से ज्यादा कर दी। पंचायत के अधोसंरचना विकास, गांव को खुले में शौच से मुक्त करना, गाँव में शराबबंदी के अलावा हाल ही में पेयजल व्यवस्था का भी नवाचार किया। इसके अलावा गाँव के कचरे से जैविक कम्पोज्ड खाद बनाने की अनोखी मिसाल कायम की है। इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों के लिए श्रीमती जोशी को चित्रकूट में केंद्रीय पंचायत मंत्री और भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रस्तुत है मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए कोदरिया की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी से किये गये नवाचारों को लेकर रीमा राय की हुई बातचीत के अंश :-

● अभी हाल ही में आपकी पंचायत द्वारा शुरू किये गये वाटर एटीएम के बारे में बताइये ?

●● हमने शुद्ध एवं शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अपनी पंचायत में दो वाटर एटीएम लगाये हैं। पहला वाटर एटीएम पंचायत भवन तथा दूसरा चलित वाटर एटीएम वाहन में लगाया गया है। इन दोनों एटीएम से बेहद रियायती दरों पर ग्रामीणों को शुद्ध एवं शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी 9 अक्टूबर से शुरू की गई इस व्यवस्था में दोनों एटीएम से प्रतिदिन लगभग 2000 लीटर शुद्ध एवं शीतल पेयजल ग्रामीण ले रहे हैं। ग्रामीणों को एक रुपये में एक लीटर, 5 रुपये में 10 लीटर तथा 10 रुपये में 20 लीटर शुद्ध एवं ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पानी प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों को एटीएम में सिक्के डालने होते हैं। ग्रामीणों की सुविधा के लिए 150 रुपये का रिचार्ज कार्ड भी दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में कार्ड की बनवाई 50 रुपये तथा 100 रुपये का बैलेंस शामिल है। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें 8 रुपये में 20 लीटर पानी मिलता है। कार्ड में राशि की सीमा समाप्त होने के बाद उसे आवश्यकतानुसार रिचार्ज भी करवाया जा सकता है।

● आपने वाटर एटीएम लगाने की पहल क्यों की ?

●● देखिए दूषित पानी कई समस्याओं की जड़ है। दूषित पानी पीने से कई बीमारियां होती हैं। इस एटीएम से पानी लेने में जितना पैसा खर्च होगा, उससे कई गुना ज्यादा तो इलाज में लग जाता है। इस व्यवस्था से पैसा और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गाँव-गाँव में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। हमारी ग्राम पंचायत भी पूर्ण स्वच्छ हो चुकी है। पूर्ण स्वच्छता का ही एक आयाम शुद्ध पेयजल भी है। इससे बीमारियों में बेहद कमी आएगी। हमने ग्राम कोदरिया में शुद्ध पेयजल की यह यूनिट प्रथमेश इंटरप्राइजेज एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में पीपीपी (पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप) मोड में शुरू की है।

● स्वच्छता के लिए आपकी पंचायत ने और क्या कार्य किये हैं।

●● स्वच्छता के लिए पंचायत को सबसे पहले खुले में शौच से मुक्त किया गया। इसके बाद घर-घर से कचरा एकत्र करके उसका जैविक कम्पोज्ड खाद बनाया जा रहा है। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि इस कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। सितम्बर 2017 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास ईश्वरीगंज में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम "स्वच्छता ही सेवा" में स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए इस नवाचार की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया तथा महामहिम के समक्ष कार्यविधि को प्रस्तुत करने का अवसर मिला।

युवा सोच से सच होते सपने

प्रत्येक मनुष्य का सपने देखने का स्वभाव होता है। पर कोई अपने लिए देखता है तो कोई दूसरों के लिए देखता है। यह भी सच है कि सपने उनके ही साकार होते हैं जो सपनों को साकार करने के प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। कुछ ऐसा ही सपना रायसेन जिले की ग्राम पंचायत तिखावन के युवा सरपंच श्री सुरेन्द्र चौधरी ने देखा है। इन्होंने सपना देखा है अपनी पंचायत को पंचायत स्तर पर होने वाले सभी कार्यों को पूर्णता प्रदान करते हुए गाँव के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने का। अपने दो साल के कार्यकाल में इन्होंने अपनी सूझ-बूझ से विकास के अनेक कार्यों को परिणाम तक पहुँचाया है। गाँव के विकास को प्रमुखता में रखते हुए पूरी लगन, मेहनत से गाँव की सूरत ही बदल दी है। सिर्फ सरकारी सहायता से ही नहीं बल्कि स्वयं के संसाधनों से भी ग्राम विकास के कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा पुनीत कार्य तो इन्होंने ग्राम पंचायत भवन के लिए अपनी जमीन देकर किया है।

श्री सुरेन्द्र चौधरी की सोच और सपनों को लेकर हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा जीवन यहीं बीता है। कई सरपंचों के कार्य देखे हैं। ग्रामवासियों की जरूरतों और समस्याओं को करीब से जाना है। दरअसल पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। गाँव की समस्याओं के निदान के लिए ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मैंने देखा कि सशक्त होती पंचायतों में हमारी पंचायत काफी पीछे थी। गाँव के विकास कार्य निष्क्रियता के चलते ठप्प थे और लोगों की समस्याएं हल नहीं होती थीं। मैंने विचार किया एक बार पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए समाजसेवा और ग्राम विकास का कार्य जरूर करूंगा। आज ग्रामवासियों के सहयोग और समर्थन से ग्राम विकास के लिए कई कार्य किये जा रहे हैं।

अपने कार्यकाल के वर्षों की उपलब्धियों को लेकर श्री चौधरी ने बताया कि सरपंच पद का दायित्व संभालते ही मेरी प्राथमिकता में ग्राम विकास और समाजसेवा रही। प्रारंभ में, गाँव के जरूरतमंदों को शासकीय स्तर पर मदद दिलाता था। खासकर कमजोर वर्ग के लोगों की प्रमुख समस्याओं को हल करता था।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत अभी तक 30 मकानों पर कार्य चल रहा है, जिनमें 20 मकान बन भी चुके हैं। इसके साथ ही अन्य लोगों को भी आवास मुहैया कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। दूसरी तरफ समग्र स्वच्छता अभियान के तहत वर्तमान में सम्पूर्ण ग्राम ओडीएफ है। गाँव में 225 शौचालयों का निर्माण किया गया है। आज कोई भी ग्रामीण खुले में शौच नहीं जाता है। इसी के तहत गाँव की सड़कों पर पानी न बहे, इसके लिए नालियों का निर्माण किया गया है। मुख्य सड़क से करीब डेढ़ किलोमीटर तक गाँव पहुंच मार्ग में हरियाली के तहत हमने इस सड़क के दोनों ओर करीब 400 पेड़ों को लगाया है। पेड़ों की सुरक्षा के लिए लोहे की जालियां लगाई गई हैं, साथ ही पौधे जीवित रहें, उसके लिए कुछ दिन के अंतराल पर टैंकर से पानी डाला जाता है। जिसका परिणाम है कि आज सभी पौधे जीवित हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत भवन का निर्माण और ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार का निर्माण प्रगति पर है। श्री चौधरी ने अपने गाँव के विकास के लिए भविष्य की योजनाएं बनायी हैं जिनमें खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गाँव में खेल का मैदान बनाना, मुक्तिधाम का निर्माण किया जाना और किसानों के लिए वेयर हाउस का निर्माण किया जाना शामिल है।

● **नवीन शर्मा**
(लेखक स्तंभकार हैं)

पंचायत भवन के लिए दान में दी जमीन

सरपंच श्री सुरेन्द्र चौधरी ने नव-निर्मित ग्राम पंचायत भवन के लिए गाँव से लगी लगभग आधा एकड़ जमीन दान में दी है। पंचायत चुनाव के समय ही इन्होंने पंचायत भवन निर्माण का संकल्प लिया था और इसके लिए अपनी निजी जमीन दान देने का ऐलान किया था। जमीन दान में देकर इन्होंने एक मिसाल कायम की है। ग्राम विकास के लिए किया गया उनका यह कार्य अनुकरणीय है।

स्व-सहायता समूह के सहयोग एवं मेहनत से बदली हाथ की लकीर

राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील में ग्राम कचनारिया के कैलादेवी स्व-सहायता समूह की सचिव सुशीलाबाई की यह सत्य कहानी है, जिसे स्वयं उनके द्वारा बताई गई है। सुशीलाबाई अनुसूचित जाति वर्ग में आती हैं गाँव के प्रारंभ में अनुसूचित जाति समुदाय की कॉलोनी है जिसमें एक छोटा सा कच्चा मकान है उसमें दो छोटे कमरे एक रसोई घर, एक छोटा सा आंगन है। इसमें उनका और उनके देवर का परिवार संयुक्त रूप से रहता है। पति एवं देवर मिस्त्री का कार्य करते हैं, देवरानी एवं स्वयं मजदूरी पर जाती हैं स्वयं के दो बेटे एवं 3 पुत्रियां हैं जो कि गाँव के स्कूल में ही पढ़ाई करते थे।

परिवार के सभी सदस्यों को मजदूरी करना पड़ती थी जिससे यह परिवार अपना जीवन यापन करता था। यह उस समय की स्थिति थी जब डी.पी.आई.पी. में यह परिवार समूह से जुड़ा था। सब मिलाकर परिवार की आय मजदूरी एवं कृषि से मासिक 8000 रुपये से 10,000 रुपये थी। समूह में जुड़ने के बाद सुशीलाबाई ने समूह से ऋण लेकर 50 प्लेट की सेंटिंग खरीदी। जो कभी उनके पति किराये से लिया करते थे और कभी-कभी मिस्त्री के रूप में भी मजदूरी किया करते थे मिस्त्री का काम करते समय उनके पति एक बार 20 फीट ऊँचाई से नीचे गिर गये थे जिससे उनका एक पैर पूरी तरह से खराब हो गया था, अब परिवार में भरण-पोषण के संकट के बादल मंडरा रहे थे। इलाज करवाने एवं परिवार को चलाने की समस्या आने लगी तभी सुशीलाबाई ने विचार बनाया कि वह समूह का पूरा पैसा जमा कर चुकी हैं और अभी बैंक लोन भी समूह को मिलने वाला है क्यों न वह समूह से एवं स्वयं के द्वारा पैसा मिलाकर सेंटिंग का सामान बढ़ा लें और उसे किराये पर दें, जिससे परिवार की आमदानी भी बढ़ेगी एवं भविष्य में स्वयं के भी काम आएगी। यह सोच कर उन्होंने 150 प्लेट की सेंटिंग और क्रय कर ली। अब सुशीलाबाई के पास 200 प्लेट की सेंटिंग हो गई थी। जिसे वह किराये पर देने लगीं। इस काम से अच्छी खासी आय होने लगी।

कुछ समय बाद 300 प्लेटों की सेंटिंग उन्होंने निजी कर ली और आज सुशीलाबाई की वर्तमान आय 15000 से 18000 रुपये मासिक हो गई है। अब धीरे-धीरे समूह का ऋण भी जमा कर दिया और पति का इलाज भी करा लिया। अपने दोनों बेटों को पढ़ाई करने इन्दौर भेज दिया है, 3 बेटियों को उच्च शिक्षा दे रही हैं। यह संयुक्त परिवार आज सुशीलाबाई की समझ एवं स्व-सहायता समूह से जुड़कर मिली आर्थिक सहायता की बदौलत अच्छा जीवन जी पाने के लिये सक्षम हो चुका है। एक समय गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल यह परिवार अब एपीएल श्रेणी में आ गया है अतः सुशीलाबाई द्वारा अपना बीपीएल कार्ड निरस्त किये जाने हेतु आवेदन भी दिया जा चुका है। इस उपलब्धि का श्रेय सुशीलाबाई अपने स्व-सहायता समूह को दे रही हैं कि बुरे वक्त में समूह ने उसकी मदद की।

सुशीलाबाई ग्राम उत्थान समिति की अध्यक्ष एवं महिला शक्ति सामुदायिक सहयोग संस्था (सी.एल.एफ.) आमल्याहाट की अध्यक्ष हैं। सुशीलाबाई में समूह से इतना उत्साह आया की वह ग्राम ज्योति के कार्य करने के लिए दूसरे जिले अलीराजपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ में स्व-सहायता समूह को प्रशिक्षण देने गयी।

स्कॉच अवॉर्ड के लिए दिल्ली गई एवं एस.आर.एल.एम. एवं डी.पी.आई.पी. के सभी जिले के स्टॉफ एवं समुदाय को भी वह सी.एल.एफ. के माध्यम से प्रशिक्षण दे रही, अपनी इस उपलब्धी से उनके परिवार, समाज, गाँव एवं एस.आर.एल.एम. एवं डी.पी.आई.पी. के जिलों में भी उनकी प्रसंशा की जा रही है।

ढाई सौ टन मूंगफली-गुड़ चिक्की हर महीने बनाकर देंगी स्व-सहायता समूहों की महिलायें

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्व-सहायता समूह के माध्यम से संगठित कर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिये मूंगफली-गुड़ चिक्की निर्माण की गतिविधि से जोड़ा गया है। मध्यान्ह भोजन के साथ वैकल्पिक पोषण आहार के रूप में 20 टन गुड़ चिक्की प्रतिदिन सप्लाई करने के लिए शिक्षा विभाग के साथ करार हुआ है, 15 अगस्त से सप्लाई शुरू हो चुकी है।

आजीविका मिशन से म.प्र. में 22.12 लाख से अधिक परिवारों को 1,93,107 लाख समूहों के माध्यम से जोड़ा गया है। 14.14 लाख परिवार आजीविका गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, इसी क्रम में 20 जिलों के 64 विकासखण्डों में गुड चिक्की निर्माण हेतु महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया प्रथम चक्र में 200 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। यह महिलाएं अपने-अपने जिलों में गुड़ चिक्की का निर्माण कर रही हैं। प्रदेश के 18470 विद्यालयों में लगभग 8.75 लाख बच्चों को वैकल्पिक पोषण आहार के रूप में खिलाये जाने के लिये 21.89 टन गुड चिक्की महीने में 12 दिन सप्लाई की जा रही है। चिक्की निर्माण कार्य की निगरानी मिशन कर्मियों के अलावा मध्यान्ह भोजन के नोडल अधिकारी भी कर रहे हैं। 15 अगस्त से 16 जिलों में एक साथ सप्लाई शुरू की जा चुकी है। आगामी 10 माह तक सप्लाई करने के लिए अग्रिम कार्यादेश समूहों को प्राप्त हो चुके हैं। यह सप्लाई खासतौर से मध्यप्रदेश के कुपोषण प्रभावित कलस्टर में प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

गुड़ चिक्की निर्माण में स्वच्छता बनाये रखने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिये जाने का प्रशिक्षण दिया गया है। अच्छी गुणवत्ता की मूंगफली एवं गुड का उपयोग कर बनाई जा रही गुड़ चिक्की निर्माण को संभावित बाजार, प्रतिस्पर्धा के मुकाबले गुणवत्ता एवं लागत कम से कम करके अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए समूह सदस्यों को लगातार प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा ताकि गतिविधि स्थाई आय का जरिया बन सके।

● **दिनेश दुबे**
(सहायक राज्य परियोजना प्रबंधक,
संचार, म.प्र. आजीविका मिशन)

समूह सदस्यों द्वारा किया जा रहा है ग्राम पंचायतों के काम का सामाजिक अंकेक्षण

सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों से जुड़े सदस्यों को सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के रूप में चिन्हित कर प्रशिक्षित किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय वर्ष वार योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आंकलन करवाया जा रहा है। यह कार्य अभी कुछ जिलों में शुरू हो चुका है। सामाजिक अंकेक्षण हेतु सामुदायिक स्रोत व्यक्ति आवंटित ग्राम पंचायतों में एक सप्ताह पूर्व सूचना कर पांच दिवस के लिये प्रवास पर जा रहे हैं। इस दौरान वे ग्राम वासियों से चर्चा कर मोबलाइजेशन करेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति का भौतिक सत्यापन एवं समुदाय के साथ चर्चा के आधार पर आंकलन कर चर्चा तथा दस्तावेजों के आधार पर जानकारी प्रपत्रों में एकत्रित कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया का अनुमोदन अंतिम दिवस में ग्राम सभा से करवाया जायेगा। सामाजिक अंकेक्षण सी.आर.पी. के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास निर्धारित की गई है। एक वर्ष तक समुदाय के बीच कार्य करने का अनुभव, सामुदायिक कार्यों की समझ तथा विश्लेषण की दक्षता होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 05 सी.आर.पी. की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं, हितग्राहीमूलक योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। मुख्य रूप से हितग्राही का चयन, पात्रता सूची के अनुसार प्राथमिकता से हुआ है या नहीं। जो राशि प्रदाय की गई है, वह सही समय पर मिली या नहीं, प्राप्त की गई राशि का उपयोग उसी काम में हुआ है या नहीं, जिस काम के लिये राशि दी गई है। कार्य की पूर्णतः गुणवत्ता, निर्माण कार्य की आवश्यकता, निर्माण कार्य में लगाये गये मजदूरों की संख्या उनको दी गई मजदूरी, निर्माण कार्य पूर्ण होने की समय सीमा, भुगतान की प्रक्रिया, लागत की जानकारी आदि बिंदु प्रमुख रूप से देखे जा रहे हैं। अलीराजपुर, शहडोल, श्योपुर, रायसेन जिलों से प्रथम चरण में 100-100 सी.आर.पी. चिन्हित किये गये थे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी चिन्हांकन एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है। पायलट के रूप में रायसेन जिले के सिलवानी विकासखण्ड की सभी 67 पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण समूह सदस्यों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

● **के.के. जोशी**
(सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, म.प्र.)

मध्यप्रदेश के आजीविका सेनेटरी नैपकिन की गुणवत्ता एवं पैकिंग बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसी

समूहों से जुड़ी महिलायें सामुदायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं को जागरूक कर सेनेटरी नैपकिन का उपयोग करने के लिये समझाईश देकर प्रोत्साहित भी कर रही हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सेनेटरी नैपकिन का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से तथा व्यक्तिगत संपर्क कर समूह सदस्यों द्वारा सेनेटरी पैड की नियमित सप्लाई की जा रही है। बाजार की तुलना में अपेक्षाकृत वाजिब दाम एवं आसानी से घर पर ही उपलब्ध होने के कारण गाँव में हर तबके की महिलाओं में पैड की स्वीकार्यता एवं मांग बढ़ी है। यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण महिलाएं केवल परंपरागत कृषि, पशुपालन आदि कामों के साथ-साथ नया काम भी कर सकती हैं।

आमतौर पर ग्रामीण गरीब परिवारों की कम पढ़ी लिखी या अशिक्षित महिलाओं के बारे में यह धारणा होती है कि वे केवल कृषि कार्य या पशु पालन जैसे परंपरागत आजीविका के काम ही कर सकती हैं। लेकिन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों से जुड़कर मानक स्तर के सेनेटरी नैपकिन बनाकर महिलाओं ने नई इबारत गढ़ी है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सुदृढ़ीकरण की नई संभावनायें दस्तक देती दिखाई दे रही हैं।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सेनेटरी नैपकिन निर्माण कार्य से जुड़कर महिलायें लाभान्वित हो रही हैं। समूह से जुड़ी सभी

महिलायें ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलायें हैं जिन्हें मिशन द्वारा आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रदेश में प्रारंभ से अब तक 1,93,107 लाख स्व-सहायता समूहों से 22.12 लाख परिवारों को जोड़ा गया है, जिनमें से 14.14 लाख से अधिक परिवार कृषि, एन.टी.एफ.टी, पशुपालन, व्यक्तिगत, सूक्ष्म उद्यम गतिविधियों से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें से 1.34 लाख से अधिक लखपति की श्रेणी में आ चुके हैं।

मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों की सदस्य अब परंपरागत आजीविका साधनों के साथ-साथ नये काम करने में न केवल रुचि दिखा रही हैं, बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने वो कर दिखाया जिसे आमतौर पर ग्रामीण महिलाओं का काम नहीं माना जाता था। मध्यप्रदेश के 25 जिलों के 151 विकासखण्डों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समूह सदस्यों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिये आजीविका गतिविधि के रूप में ग्राम स्तर पर सेनेटरी नैपकिन निर्माण इकाई स्थापित कराई गई है।

इस काम को करने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकीं 2285 महिलाओं को इन इकाईयों से जोड़ा गया है। इनके द्वारा प्रति माह लगभग ढाई लाख पैकेट का निर्माण किया जा रहा है। सेनेटरी नैपकिन बनाने का काम समूह सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत के साथ-साथ सामूहिक रूप से भी किया जा रहा है। आजीविका सेनेटरी पैड की गुणवत्ता मानक स्तर की है तथा पैकिंग भी आकर्षक है जो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुकाबले कम नहीं है।

समूहों से जुड़ी महिलायें सामुदायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं को जागरूक कर सेनेटरी नैपकिन का उपयोग करने के लिये समझाईश देकर प्रोत्साहित भी कर रही हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सेनेटरी नैपकिन का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से तथा व्यक्तिगत संपर्क कर समूह सदस्यों द्वारा सेनेटरी पैड की नियमित सप्लाई की जा रही है। बाजार की तुलना में अपेक्षाकृत बाजिव दाम एवं आसानी से घर पर ही उपलब्ध होने के कारण गाँव में हर तबके की महिलाओं में पैड की स्वीकार्यता एवं मांग बढ़ी है। यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण महिलायें केवल परंपरागत कृषि, पशुपालन आदि कामों के साथ-साथ नया काम भी कर सकती हैं।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीडियो कांफ्रेंस में दिये गए निर्देश

दिनांक 14.09.2017

अ. कलेक्टर के साथ :

1. 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर, 2017 तक प्रदेश में "स्वच्छता ही सेवा" एवं "पानी रोको" अभियान संचालित किया जाए। इस हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय विकास विभाग ने निर्देश जारी किये हैं।
2. अल्प वर्षा की पृष्ठभूमि में पेयजल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान ध्यान दिया जाए। आवश्यकतानुसार अग्रिम तैयारी की जाए।
3. अल्प वर्षा की पृष्ठभूमि में रबी में कम पानी अथवा बिना पानी की फसलों को लेने के लिए कृषकों में जागरुकता पहुँचाई जाए।

ब. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के साथ :

1. स्वच्छ भारत मिशन :

1.1 "स्वच्छता ही सेवा अभियान" के लिए स्वच्छता रथ इस प्रकार संचालित किए जाएं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में न्यूनतम 3 घंटे रथ रुककर प्रचार-प्रसार कर सके।

1.2 अधिकाधिक ग्राम/पंचायत/विकास खंड/जिले को 02 अक्टूबर को ओडीएफ घोषित किया जाए बशर्ते कि उनमें भारत सरकार के पोर्टल पर शौचालय विहीन घरों की संख्या शून्य हो गई हो।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना :

2.1 राजगढ़, सागर, उज्जैन एवं गुना जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। सिंगरौली, श्योपुर, सीधी, हरदा एवं भिण्ड जिले की प्रगति बहुत ही कमजोर है इसमें शीघ्र सुधार किया जाए।

2.2 जिन जिलों में 1500 से कम तथा जनपदों में 150 से कम आवास पूर्ण हुए हैं उनकी समीक्षा की गई। सुधार के लिए सलाह दी गई।

2.3 मुख्यमंत्री आवास मिशन में आवास पूर्णता एवं रिकवरी की समीक्षा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपने स्तर पर करें।

3. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :

3.1 कार्यक्रम से सम्बंधित जिन SHGs/रसोइया/पीटीए के खाते सहकारी बैंकों या नागरिक बैंकों में हैं उनमें धनराशि पहुंचाने में ज्यादा विलम्ब हो रहा है। इनके खाते वाणिज्यिक/राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुलवाये जाएं, ताकि भुगतान में विलम्ब न हो।

3.2 इस माह का राशन 20 सितम्बर तक Online जारी किया जाए।

3.3 30 सितम्बर तक की अवधि के लिए रसोइयों का मानदेय भुगतान 25 सितम्बर तक Online किया जाए।

3.4 01 अक्टूबर से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त कार्य Online होगा। कोई पत्राचार एवं कागजी लिखा-पढ़ी नहीं की जाए।

4. पंच परमेश्वर :

4.1 सीसी सड़क, पक्की नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन, आदि के लिए ग्राम पंचायतों को रायल्टी मुक्त रेत एवं गिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। जिन स्थानों पर रेत/गिट्टी के परिवहन की दूरी ज्यादा हो वहां जिला पंचायत की निधि से डम्पर/ट्रेक्टर किराये पर लगाने के लिए विकास आयुक्त से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनुमति लें।

4.2 जिला पंचायतों में कार्यरत् डीआरडीए के अमले का वेतन भुगतान राज्य स्तर के खाते से किया जाएगा। जानकारी गूगल शीट में भेजें।

4.3 जिला एवं जनपद पंचायत के अन्य समस्त अमले के वेतन का भुगतान अगले माह से सीधे राज्य के खाते से किया जाएगा। संचालक, पंचायत द्वारा निर्धारित गूगल शीट में जानकारी भेजें।

5. मनरेगा :

5.1 निर्माणाधीन मोक्षधाम एवं खेल मैदान यथाशीघ्र पूर्ण कराएं। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा स्वयं निरीक्षण/मॉनिटरिंग करें।

5.2 वृक्षारोपण परियोजना के तहत जहां पौधरक्षक का कार्य संतोषजनक नहीं हो वहां पौधरक्षकों को बदला जाए।

5.3 दतिया, भोपाल, भिण्ड, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच एवं सीहोर जिले में जियोटेगिंग की प्रगति नगण्य है। सुधार करें।

दिनांक 21/09/2017

1. नल-जल योजनाएं :

1.1 जिन नल-जल योजनाओं की मरम्मत के लिए निविदा प्राप्त नहीं हुई हैं उनमें पुनः निविदा आमंत्रित करने के लिए PHE ने गारंटी अवधि 02 वर्ष से कम करके एक वर्ष की

है।

1.2 रु. 20.00 लाख तक के कार्यों के लिए TS हेतु EE, PHE को अधिकृत किया गया है। रु. 20.00 लाख तक प्रशासकीय स्वीकृति जिला स्तर से ही दी जाएगी।

1.3 निविदाएं ई-टेण्डर से ही बुलाई जाएंगी लेकिन रु. 20.00 लाख तक की निविदाएं जिला स्तर पर खोली एवं स्वीकृत की जाएंगी।

1.4 CEO, ZP समीक्षा कर सुनिश्चित करें कि :

(अ) सभी नल-जल योजनाएं चालू रहें।

(ब) नल-जल योजनाओं की मरम्मत आदि की निविदाएं यथाशीघ्र आमंत्रित कर एजेंसी निर्धारण 31 अक्टूबर के पूर्व हो जाए।

(स) ग्राम पंचायतें नल-जल योजनाओं को प्रतिदिन चालू एवं बंद करने की व्यवस्था करें। इस हेतु सचिव/सहायक सचिव को पाबंद किया जा सकता है।

2. पुरानी आवास योजनाएं :

2.1 CEO, ZP अपूर्ण आवासों की जनपदवार समीक्षा करें और 31 अक्टूबर तक आवास पूर्णता के लिए लक्ष्य निर्धारित कर गूगलशीट में 30 सितम्बर तक दर्ज करें।

2.2 SC/ST वर्ग के जिन हितग्राहियों के आवास अप्रारम्भ हैं अथवा नींव स्तर से ऊपर नहीं बने हैं उनके आवास पूर्ण कराने के लिए निम्न कार्रवाई की जा सकती है :

(i) यदि वे PMAY के तहत पात्र हैं तो पूर्व में दी गई राशि समायोजित करते हुए स्वीकृति दी जा सकती है।

(ii) प्रत्येक प्रकरण में निर्णय गुण दोष पर PMAY की जिला स्तरीय समिति ले।

ग्रायांसे) के खाते में भेजी जाए।

5.3 किसी भी दशा में जिला/जनपद पंचायत के खाते में धनराशि नहीं भेजी जाए।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना :

6.1 उज्जैन एवं राजगढ़ जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। नीचे से 06 जिलों ने आश्वस्त किया कि अगली VC तक वे 2000 आवास पूर्ण करा लेंगे।

6.2 आवासों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। लक्ष्य अथवा पुरस्कार की दौड़ में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाए। ध्यान रखें कि अपूर्ण आवास को पूर्ण बताने की दशा में जनपद/जिला पंचायत पुरस्कार योजना के तहत अपात्र हो जाएंगे।

6.3 मिस्त्री प्रशिक्षण विभागीय तौर से EE, RES से कराने की व्यवस्था की गई है। CEO, ZP जिले में प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ कराएं और प्रशिक्षण के दौरान स्वयं निरीक्षण भी करें।

7. स्वच्छ भारत मिशन :

7.1 जिला शाजापुर एवं होशंगाबाद के 2 अक्टूबर को ODF घोषित होने की आवश्यक तैयारी समय पर पूरी करें।

7.2 जिला अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, रायसेन, रीवा एवं सीधी अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस पर जिलों को ODF घोषित करने के लिए आश्वस्त किया। खंडवा, मंदसौर, रतलाम एवं विदिशा जिलों को दिसम्बर माह में ODF घोषित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करें।

7.3 भारत सरकार के MIS में दर्ज दिव्यांगों के शौचालय विहीन घरों में शौचालय निर्माण की समीक्षा CEO, ZP पृथक से कर लें।

8. पंचपरमेश्वर :

8.1 संचालक, पंचायत द्वारा बार-बार स्मरण कराने के बाद भी कुछ CEO, JPs ने भवन विहीन पंचायतों की जानकारी गूगल शीट पर दर्ज नहीं की है। कल दोपहर तक जो CEO, JP भवन विहीन पंचायतों की जानकारी दर्ज नहीं करेंगे उन्हें 02 वेतनवृद्धि रोकने हेतु SCN जारी किया जाए।

8.2 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चाहा है कि 01 से 15 अक्टूबर में "ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता" पखवाड़ा आयोजित किया जाए। भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट http://rural.nic/ documents/ presentations पर है। CEO, ZP एक प्रति निकालकर तैयारी प्रारंभ करें। राज्य स्तर से पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

9. मनरेगा :

जिन जिलों ने लेबर बजट के 50% से कम उपयोग किया है उनके वार्षिक बजट के उपयोग की तैयारी की समीक्षा की गई।

दिनांक 28.9.2017

1. आजीविका मिशन (मिशन अन्त्योदय) :

1.1 दिनांक 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक "ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा" मनाया जाए। विस्तृत निर्देश पृथक से भेजे गए हैं। भारत सरकार द्वारा जारी मोबाइल एप से पखवाड़े की गतिविधियों की जानकारी अपलोड की जाए। इस हेतु चयनित C.R.P. एवं G.R.S. को प्रशिक्षण दिया गया है। पखवाड़े में प्रचार-प्रसार के लिए I.E.C. सामग्री पंचायत विभाग के पोर्टल पर अपलोड की गयी है। जिला पंचायत बैंक के खाते से रुपये 5000/- प्रति विकासखण्ड के हिसाब से व्यय कर मुद्रण कराया जाए।

1.2 CEO, ZP सुनिश्चित करें कि आजीविका मिशन की नस्ती पर निर्णय एक कार्य दिवस में ले लिया जाए। आवश्यकता अनुसार मिशन के जिला अधिकारी को व्यक्तिशः बुलाकर उनसे योजना संबंधी जानकारी ली जाए। पूर्व अग्रिम का समायोजन हो जाने के पश्चात आजीविका गतिविधियों के लिए आवश्यकतानुसार अग्रिम दिया जाए।

1.3 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। बैंकों को लक्ष्य से अधिक प्रकरण न भेजें। प्रकरण भेजने के पहले बैंकों के साथ प्रकरणों की पूर्व समीक्षा कर लें ताकि बैंकों से शत-प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत हों।

1.4 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में बड़ी संख्या में राजमिस्त्रियों का 45 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के प्रारंभ होते ही सभी राजमिस्त्रियों को टूलकिट देने के लिए प्रकरण बनाकर बैंकों को स्वीकृति भेजी जाए। इस हेतु प्रशिक्षण में बैंकों के प्रबंधकों को बुला लिया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक राजमिस्त्री को टूलकिट उपलब्ध हो। मानक टूलकिट का निर्धारण E.N.C., RRDA तत्काल करें।

1.5 ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की गुणवत्ता के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के तहत प्रति विकासखण्ड न्यूनतम दो रोड रोलर के प्रकरण स्वीकृत कराकर 31 अक्टूबर तक रोड रोलर की

व्यवस्था कराई जाए। CEO, ZP इसे व्यक्तिगत लक्ष्य मानें।

2. स्वच्छ भारत मिशन :

2.1 प्रेरकों के मानदेय तथा स्वच्छता सम्मान आदि IEC कार्यों के लिए जिले में निर्मित शौचालयों के लिए बनती IEC राशि का 50% (शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि का 1.875%) उपलब्ध कराया जाए। इस वित्तीय वर्ष में निर्मित शौचालयों के लिए जिलेवार बनती राशि में इस वर्ष दी गयी I.E.C. राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि जिलों को जारी की जाए।

2.2 प्रेरकों के मानदेय निर्धारण के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। निर्देश दिए गए कि किसी निश्चित न्यूनतम मासिक मानदेय भुगतान की व्यवस्था अनुमत्य (permissible) नहीं है। मानदेय का निर्धारण कार्य आधारित हो। वर्ष 2017-18 में किस कार्य के लिए कितना पारिश्रमिक दिया जाए यह जिले उन्हें IEC में उक्त बिन्दु 2.1 के अनुसार मिलने वाली राशि के आधार पर नियत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

2.3 स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान प्रारंभ किए गए सभी शौचालयों का निर्माण अक्टूबर माह में अनिवार्यतः पूर्ण कराया जाए।

2.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायतों के समूह बनाकर ईंधन चलित वाहन से रूटचार्ट बनाकर ठोस अपशिष्ट एकत्रित करने और क्लस्टर केन्द्र बनाकर उसके sorting की व्यवस्था पर विचार किया जाए।

2.5 ग्रामों में कचरा डालने के लिए सार्वजनिक जगह सुनिश्चित नहीं की जाए। सामुदायिक डस्टबिन से गंदगी

15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलाया जायेगा 'स्वच्छता ही सेवा' – राष्ट्रव्यापी अभियान

विकास आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक 2933/22/वि-7/पंग्रावि/एसबीएम (जी)/2017 **भोपाल, दिनांक 13.09.2017**

प्रति,

1. **समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।**
2. **समस्त कलेक्टर, म.प्र.**
3. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश**

विषय- स्वच्छता ही सेवा-राष्ट्रव्यापी अभियान दिनांक 15 सितम्बर 2017 से 02 अक्टूबर, 2017

स्वच्छ भारत अभियान की तीसरी वर्षगांठ पर मान. प्रधानमंत्रीजी ने स्वच्छ भारत मिशन-जन आंदोलन की ऊर्जा स्फूर्ति करने के उद्देश्य से 'स्वच्छता ही सेवा' राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान दि. 15 सितम्बर से 02 अक्टूबर 2017 तक आयोजित करने का संकल्प लिया है। स्वच्छता ही सेवा के साथ मा. मुख्यमंत्रीजी ने अल्पवर्षा से उत्पन्न परिस्थितियों में नदी नालों में बहते पानी को रोकने के लिए जन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अतः 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के साथ-साथ प्रदेश भर में 'जल रोको' जन आंदोलन चलाया जाना है।

2. दि. 15 सितंबर से 02 अक्टूबर 2017 तक की अवधि में 'स्वच्छता ही सेवा' एवं 'जल रोको' अभियान के क्रियान्वयन के लिए सुझावात्मक समयचक्र निम्नानुसार है :-

2.1 दिनांक 15 सितंबर 2017 :- जिला मुख्यालय पर अभियान का शुभारंभ किया जाए। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए :-

(i) मान. मंत्री, सांसद, विधायक, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सहित जागरूक नागरिकों और जिला स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए।

(ii) अपरान्ह 3.35 बजे परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप में स्वच्छता की शपथ ली जाए।

(iii) 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान अवधि की गतिविधियों की जानकारी दी जाए।

(iv) 'जल रोको अभियान' का शुभारंभ किसी भी एक नदी/नाले में श्रमदान करते हुए बोरीबंधान कर किया जाए।

(v) शुभारंभ कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इस हेतु जिले में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारी की सेवाएं ली जाएं।

(vi) जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित कराकर अधिकाधिक व्यक्तियों को स्वच्छता शपथ दिलाई जाए।

2.2 दिनांक 17 सितंबर 2017 :- दि. 17 सितंबर 2017 को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन :-

(i) शौचालय विहीन घरों में श्रमदान कर ट्विन-पिट तकनीकी अपनाते हुए शौचालय निर्माण हेतु गड्ढे खोदे जाएं और शौचालय निर्माण प्रारंभ कराए जाएं।

(ii) प्रत्येक ग्राम में नदी/नाले में बहते पानी को रोकने के लिए नालाबंधान का एक कार्य श्रमदान कर प्रारंभ कराया जाए। बोरीबंधान कार्य के लिए महात्मा गाँधी नरेगा के तहत स्वीकृति दी जाए। (बोरीबंधान पर मनरेगा के तहत लगी रोक 15 दिवस के लिए शिथिल करने का निर्णय लिया गया है)।

(iii) श्रमदान में मान. मंत्री, सांसद, विधायक, जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभागीय स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों, जागरूक नागरिकों एवं आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि जन अभियान 'स्वच्छता ही सेवा' एवं 'जल रोको' अभियान की अवधारणा को मूर्त रूप देना सुनिश्चित हो।

(iv) प्रातः 11.30 बजे दूरदर्शन पर 'टॉयलेट एक प्रेम कथा' का प्रसारण होगा। फिल्म देखने की व्यवस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत में की जाए। फिल्म के प्रसारण की जानकारी आम जनता को दी जाए ताकि वे उनके घरों में भी फिल्म देख सकें।

2.3 स्वच्छता रथ :- दि. 17 सितंबर से 02 अक्टूबर 2017 तक (त्योहार अवधि छोड़कर) 10 दिवस के लिए स्वच्छता रथ यात्रा चलाई जाए। इस हेतु :-

(i) जिलेवार स्वीकृत रथ संख्या तथा राशि विवरण परिशिष्ट-2 अनुसार है।

(ii) स्वच्छता रथ में :-

(a) स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग्स लगाए जाएं। स्वच्छता संबंधी ऑडियो/वीडियो प्रसारण की सुविधा हो।

(b) जल रोको अभियान से संबंधित गाने एवं संदेश प्रसारित किए जाएं।

(c) अल्पवर्षा से उत्पन्न परिस्थिति में पानी रोकने के साथ-साथ पेयजल हेतु पानी सुरक्षित करने और रबी फसल में जल की उपलब्धता के मुताबिक उपयुक्त फसलों का चयन करने का संदेश दिया जाए।

(iii) स्वच्छता रथ का रूट चार्ट एवं एवं समयचक्र इस प्रकार बनाया जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में रथ न्यूनतम 3 घंटे रुककर 'स्वच्छता ही सेवा' एवं 'जल रोको' अभियान के संबंध में जानकारी का आदान-प्रदान करें।

(iv) प्रत्येक रथ के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के क्लस्टर अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए ताकि वह पूरे समय तक रथ यात्रा में रहे।

(v) रथ यात्रा का शुभारंभ मान. मंत्री, विधायक, जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जो भी उपलब्ध हों, उनसे अपने-अपने क्षेत्र में कराया जाए।

2.4 दिनांक 18 से 24 सितंबर 2017 :-

(i) इस अवधि में जनभागीदारी से प्रत्येक ग्राम में सफाई अभियान चलाया जाए। शासकीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई की जाए। शौचालय विहीन घरों में शौचालय निर्माण के लिए अधिकाधिक परिवारों को प्रेरित कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाएं।

(ii) खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर ऐसे व्यक्तियों से वन टू वन संवाद कर उसके दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए खुले में शौच नहीं करने की शपथ दिलाई जाए।

(iii) ओडीएफ हो चुकी ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य प्रारंभ कराए जाएं।

(iv) आबादी क्षेत्र में निर्मित सीसी सड़कों में जिन स्थानों पर नालियाँ न हों वहाँ पक्की नाली निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए।

2.5 दिनांक 25 सितंबर 2017 को :-

(अ) विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएं। ग्राम सभाओं का एजेण्डा निम्नानुसार रहेगा :-

(i) स्वच्छता एवं ओडीएफ।

(ii) जल रोको।

(iii) अल्पवर्षा के परिप्रेक्ष्य में पेयजल एवं अल्प पानी की रबी फसल।

(ब) सभी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में मध्यान्ह भोजन के पूर्व प्रत्येक कर्मचारी, शिक्षक, सहायक एवं बालक/बालिकाओं को साबुन से हाथ धोने का सामूहिक हाथ धुलाई कार्यक्रम संपन्न किया जाए।

2.6 दिनांक 26 से 30 सितंबर 2017 :-

(i) स्वच्छता विषय पर जनजागरुकता कार्यक्रम यथा - प्रभातफेरी, भजन मण्डली, संगोष्ठी आदि आयोजित किए जाएं।

(ii) ओडीएफ संबंधी प्रेरकों, छात्र/छात्राओं, टोलियों, स्वयंसेवियों से कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं।

(iii) संलग्न परिशिष्ट-3 में वर्णित पुरस्कारों के लिए चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाए।

2.7 दिनांक 02 अक्टूबर 2017 :- 02 अक्टूबर स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन जिला स्तर पर :-

(i) मुख्यमंत्री स्वच्छता समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाए।

(ii) प्रत्येक जनपद पंचायत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बालक/बालिकाओं, भजन मण्डलियों, सफाई कर्मियों एवं सरपंचों आदि को आमंत्रित कर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाए।

(iii) अधिकाधिक जिले/जनपद/ग्राम पंचायत/ग्राम को ओडीएफ घोषित किया जाए बशर्ते की वे ओडीएफ हो गए हों तथा भारत सरकार के पोर्टल पर शौचालय विहीन घरों की संख्या शून्य हो गई हो।

3. 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान की दैनिक प्रगति की जानकारी भारत सरकार को भेजी जाना है और 'जल रोको' अभियान की प्रगति की दैनिक जानकारी राज्य स्तर पर संकलित की जाना है। अतः दोनों अभियानों से संबंधित गतिविधियों के स्मार्ट फोन से फोटो लिए जाएं और प्रगति की जानकारी तथा फोटो विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए जाएं।

संलग्न- 3 परिशिष्ट।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-1

"स्वच्छता ही सेवा" शपथ

मैं.....अपने अंत:करण से यह दृढ़ संकल्प करता/करती हूँ कि मैं स्वयं को एक स्वच्छ, स्वस्थ और नवीन भारत के निर्माण एवं दिनांक 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2017 तक चल रहे "स्वच्छता ही सेवा" जन-आन्दोलन के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित करता/करती हूँ जिसमें मैं,

- घर, विद्यालय, कॉलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, रेलवे और बस स्टेशन, तालाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता को बढ़ावा दूँगा/दूँगी।
- स्वयं द्वारा और अन्य लोगों, जो स्वयं के लिए व्यवस्था करने में असमर्थ है, दो गड्ढा शौचालय के निर्माण में सहायता कर गाँव और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त करने में योगदान दूँगा/दूँगी।
- स्वयं द्वारा और अन्य लोगों, जो स्वयं के लिए व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, दो गड्ढा शौचालय के निर्माण में सहायता कर गाँव और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त करने में योगदान दूँगा/दूँगी।
- शौचालयों के प्रयोग, हाथों की सफाई और अन्य स्वच्छता आदतों को अपना कर स्वच्छता हेतु व्यवहार परिवर्तन में भाग लूँगा/लूँगी।
- रेड्यूस, रिसाइकिल और रियूज़ के सिद्धांत को अपनाते हुए ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दूँगा/दूँगी।

परिशिष्ट-2

जिलावार रथों की संख्या एवं स्वीकृति राशि

क्र.	जिला	कुल ग्राम पंचायत	रथों की संख्या	राशि रुपये (लाख में) प्रति रथ रु. 50 हजार
1.	आगर मालवा	227	6	3.00
2.	अलीराजपुर	288	8	4.00
3.	अनूपपुर	282	8	4.00
4.	अशोकनगर	333	10	5.00
5.	बालाघाट	690	20	10.00
6.	बड़वानी	416	12	6.00
7.	बैतूल	556	16	8.00
8.	भिण्ड	447	13	6.50
9.	भोपाल	187	5	2.50
10.	बुरहानपुर	167	5	2.50
11.	छतरपुर	558	16	8.00
12.	छिन्दवाड़ा	784	22	11.00
13.	दमोह	460	13	6.50
14.	दतिया	290	8	4.00
15.	देवास	495	14	7.00
16.	धार	761	22	11.00
17.	डिण्डोरी	364	10	5.00
18.	गुना	425	12	6.00
19.	ग्वालियर	256	7	3.50
20.	हरदा	213	6	3.00

क्र.	जिला	कुल ग्राम पंचायत	रथों की संख्या	राशि रुपये (लाख में) प्रति रथ रु. 50 हजार
21.	होशंगाबाद	424	12	6.00
22.	इंदौर	312	9	4.50
23.	जबलपुर	515	15	7.50
24.	झाबुआ	375	11	5.50
25.	कटनी	407	11	5.50
26.	खंडवा	422	12	6.00
27.	खरगोन	594	17	8.50
28.	मंडला	486	14	7.00
29.	मंदसौर	440	13	6.50
30.	मुरैना	478	14	7.00
31.	नरसिंहपुर	446	13	6.50
32.	नीमच	236	7	3.50
33.	पन्ना	395	11	5.50
34.	रायसेन	494	14	7.00
35.	राजगढ़	622	18	9.00
36.	रतलाम	418	12	6.00
37.	रीवा	827	24	12.00
38.	सागर	755	22	11.00
39.	सतना	692	20	10.00
40.	सीहोर	497	14	7.00
41.	सिवनी	645	18	9.00
42.	शहडोल	391	11	5.50
43.	शाजापुर	326	9	4.50
44.	श्योपुर	225	6	3.00
45.	शिवपुरी	600	17	8.50
46.	सीधी	400	11	5.50
47.	सिंगरौली	316	9	4.50
48.	टीकमगढ़	459	13	6.50
49.	उज्जैन	609	17	8.50
50.	उमरिया	234	7	3.50
51.	विदिशा	577	16	8.00
	कुल योग	**22816**	**650**	**325.00**

परिशिष्ट-3

"स्वच्छता ही सेवा" अभियान - पुरस्कार योजनाएं

1. स्वच्छ ग्राम पंचायत पुरस्कार :

(क) पुरस्कार : प्रथम पुरस्कार रु. 50,000
द्वितीय पुरस्कार रु. 40,000
तृतीय पुरस्कार रु. 30,000

(ख) पुरस्कार संख्या : 80 से ज्यादा ग्राम पंचायत वाली जनपद में प्रत्येक श्रेणी के 02 पुरस्कार तथा शेष जनपदों में प्रत्येक श्रेणी का एक-एक पुरस्कार

(ग) चयन के मापदण्ड

उपलब्धता	अधिकतम अंक
ODF होना	20
ODF निरन्तरता	30
सार्वजनिक स्थल सफाई	20
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	10
तरल अपशिष्ट प्रबंधन	20
कुल योग	**100**

(घ) चयन प्रक्रिया : (1) 20 से 29 सितम्बर के मध्य आयोजित होने वाली जनपद की सामान्य समिति की बैठक में जनपद सदस्यों से पुरस्कार हेतु स्वच्छता में उत्कृष्ट उनके क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के नाम प्राप्त किये जाएं।

(2) मुख्यमंत्री स्वच्छता सम्मान के लिये गठित चयन समिति उक्त मापदंडों पर चयन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दि. 30 सितम्बर तक सूचित करें।

(च) पुरस्कार राशि का वितरण : 02 अक्टूबर 2017 को जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण निम्नानुसार किया जाए :-

(1) 20 प्रतिशत राशि पुरस्कृत ग्राम पंचायत के सक्रिय सफाई कर्मियों को नगद वितरित की जाए।

(2) 20 प्रतिशत राशि पुरस्कृत ग्राम पंचायत के विद्यालयों के पालक शिक्षक समिति के प्रतिनिधियों को चेक से दी जाए।

(3) शेष राशि का 60 प्रतिशत राशि सरपंच के नाम से चेक द्वारा सरपंच को दी जाए। यह राशि पंचायत निधि का भाग नहीं होगी तथा सरपंच स्वविवेक से यह राशि स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत करने अथवा अन्यथा स्वच्छता कार्य में उपयोग कर सकेंगे।

2. भजन मंडली को पुरस्कार :

(क) भजन कीर्तन सामग्री क्रय करने के लिये प्रति भजन मंडली रु. 10,000/- (दस हजार) का नगद पुरस्कार।

(ख) पुरस्कार संख्या :

(i) ODF जनपद पंचायत की दशा में 80 से ज्यादा ग्राम पंचायतों वाली जनपद में 5 एवं अन्य ODF जनपदों में 3 पुरस्कार

(ii) नॉन ODF जनपद पंचायतों की दशा में प्रति जनपद 3 पुरस्कार ODF ग्राम पंचायतों में सक्रिय भजन मंडली के लिए।

3. बाल टोली पुरस्कार :

प्रत्येक जनपद पंचायत में ODF ग्राम पंचायतों में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ 3 बाल टोलियों को खेल-कूद सामग्री क्रय करने के लिए प्रति बाल टोली रु. 5,000/- (पांच हजार) का नगद पुरस्कार।

4. किशोरी स्वच्छता पुरस्कार :

प्रत्येक जनपद पंचायत के ODF ग्राम पंचायतों में स्वच्छता का उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 किशोरियों को रु. 1,000/- (एक हजार) प्रति किशोरी।

टीप :- उपरोक्त सभी पुरस्कार 2 अक्टूबर 2017 को जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत सभी व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए दिए जाएं।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश

जनपद पंचायतों को सामुदायिक भवनों के निर्माण की मिली स्वीकृति

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./निर्माण-214/2017/10838 **भोपाल, दिनांक 11.09.2017**

//आदेश//

एतद द्वारा संबंधित जनपद पंचायत के खाते में उपलब्ध राशि से सामुदायिक भवनों के निर्माण कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:-

क्र.	स्थान	ग्राम पंचायत	ज.पं.	प्रकार	लागत राशि (रु. लाख में)		
					भवन	बाउण्ड्रीवाल	योग
1.	ग्राम माधौ	जरिया खिरिया	रहली	टाईप-3	21.00	4.50	25.50
2.	ग्राम संजरा	संजरा	रहली	टाईप-2	17.00	3.00	20.00
3.	ग्राम डांगी डहर में भटुआ टोला	खैजरा उद्देत	सागर	टाईप-1	10.00	2.00	12.00
4.	ठाकुरबाबा मंदिर के पास	जरुवाखेड़ा	राहतगढ़	टाईप-3	21.00	4.50	25.50
5.	अबार माता मंदिर के पास	सौरई	बड़ा मलहरा	टाईप-3	21.00	4.50	25.50
6.	ग्राम मडावनमार	हडली	मालथौन	टाईप-1	10.00	2.00	12.00

शर्तें :

2.1 निर्माण एजेन्सी मान. क्षेत्रीय विधायक के परामर्श अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नियत करे। ग्राम पंचायत को एजेन्सी नियत किये जाने की दशा में ग्राम पंचायत के लिये 15.00 लाख की सीमा शिथिल मानी जाये।

2.2 निर्माण प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के पत्र क्र. 3773, दि. 14.08.2017 द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों एवं अवयवों के अनुसार कराया जाए। प्रमुख अभियंता के इस पत्र में तकनीकी मापदंड नियत कर दिए जाने से पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

2.3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराएं। इस हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं से पर्यवेक्षण कराया जाये।

2.4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आवश्यक समझे तो शासन के किसी भी विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री अथवा वरिष्ठ स्तर के अभियंता से आवश्यकतानुसार तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मदद की व्यवस्था कर सकते हैं। इस हेतु प्रति भवन/प्रति निरीक्षण पारिश्रमिक तय कर प्रति भवन की स्वीकृत लागत में से अधिकतम एक प्रतिशत व्यय किया जा सकता है।

2.5 प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने बाउण्ड्रीवाल की मानक लागत रुपये 3,550/- प्रति रनिंग मीटर निर्धारित की है, जिसमें गेट की लागत शामिल है। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्धारित तकनीकी अवयवों एवं मापदण्डों के अनुसार कराया जाए।

2.6 भवन निर्माण 31.03.2018 तक पूर्ण करना होगा।

3. निर्माण का चरणबद्ध मानक मूल्यांकन प्रमुख अभियंता के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.08.2017 द्वारा नियत किया गया है:-

सामुदायिक भवन	**मानक लागत**	**मानक मूल्यांकन (लाख रु.)**				
		प्लिंथ स्तर तक	**छत स्तर तक**	**छत डलने पर**	**भवन पूर्ण होने पर**	**फिनिशिंग एवं फिटिंग पूर्ण होने पर**
टाईप-1	10.00	2.00	2.00	2.50	2.50	1.00
टाईप-2	17.00	3.40	3.40	4.25	4.25	1.70
टाईप-3	22.50	4.50	4.50	5.62	5.62	2.28

4. ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी नियत करने की दशा में से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधित ग्राम पंचायत को उपरोक्त स्वीकृत राशि 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा करें एवं पंचायतराज संचालनालय को अवगत कराएं:-

(राशि रु. लाख में)

		टाईप-1	**टाईप-2**	**टाईप-3**	
प्रथम किश्त	40 प्रतिशत	4.00	6.80	9.00	स्वीकृति के साथ
द्वितीय किश्त	40 प्रतिशत	4.00	6.80	9.00	छत स्तर तक निर्माण पर
तृतीय किश्त	20 प्रतिशत	2.00	3.40	4.50	पूर्णता उपरांत
अंतिम किश्त	बाउण्ड्रीवाल की लागत	-	-	-	पूर्णता उपरांत

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(शमीम उद्दीन)
संचालक

छतरपुर जिले की 40 थाना/चौकियों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का होगा निर्माण

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

दिनांक 07.09.2017

//आदेश//

क्रमांक 2908/एसबीएम/बी-7/2017 : छतरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रवृत्ति बंद करने और स्वच्छता को ग्रामवासियों की आदत में लाने के उद्देश्य से कलेक्टर छतरपुर के प्रस्ताव अनुसार निम्न तालिका में दर्शाए 40 थाना/चौकियों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रति परिसर राशि रु. 2.00 लाख के मान से कुल रु. 80 लाख की दी जाती है:-

क्र.	थाना/चौकी का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	क्र.	थाना/चौकी का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	चौकी लुगासी	नौगांव	लुगासी	21	चौकी पिपट	बिजावर	पिपट
2.	चौकी गरोली	नौगांव	गरोली	22	चौकी पडरिया	छतरपुर	पडरिया
3	चौकी काकुनपुरा	नौगांव	काकुनपुरा	23	थाना किशनगढ़	बिजावर	किशनगढ़
4	थाना अलीपुरा	नौगांव	अलीपुरा	24	चौकी कुपी	बिजावर	कुपी
5	चौकी अकौना	राजनगर	अकौना	25	थाना शाहगढ़	बिजावर	शाहगढ़
6	चौकी बमीठा	राजनगर	बमीठा	26	चौकी जटाशंकर धाम	बिजावर	डिलारी
7	चौकी सीलोन	राजनगर	सीलोन	27	थाना मातगुवां	छतरपुर	मातगुवां
8	चौकी चन्द्रनगर	राजनगर	चन्द्रनगर	28	चौकी सेंदपा	बड़ामलहरा	सेंदपा
9	चौकी पठा	लवकुशनगर	पठा	29	चौकी महराजगंज	बड़ामलहरा	महाराजगंज
10	चौकी अटकोंहा	लवकुशनगर	अटकोंहा	30	चौकी दरगुवा	बकस्वाहा	दरगुवा
11	चौकी बछोन	लवकुशनगर	बछोन	31	चौकी करी	बड़ामलहरा	करी
12	थाना हिनौता	लवकुशनगर	हिनौता	32	थाना गुलगंज	बिजावर	गुलगंज
13	थाना बंसिया	लवकुशनगर	बंसिया	33	चौकी बांधाचमरोई	बड़ामलहरा	बांधाचमरोई
14	थाना सरबई	गौरिहार	सरबई	34	थाना बाजना	बकस्वाहा	बाजना
15	थाना गोयरा	गौरिहार	गौरिहार	35	थाना रानीताल	बड़ामलहरा	रानीताल
16	थाना गौरिहार	गौरिहार	गौरिहार	36	थाना बमनौरा	बड़ामलहरा	बमनौरा
17	चौकी पहरा	गौरिहार	पहरा	37	चौकी रामटौरिया	बड़ामलहरा	रामटौरिया
18	थाना प्रकाश बम्हौरी	गौरिहार	प्रकाश बम्हौरी	38	चौकी भगवां	बड़ामलहरा	भगवां
19	चौकी खैराकला	बिजावर	खैराकला	39	चौकी बम्हौरी	बकस्वाहा	बम्हौरी
20	थाना ईशानगर	छतरपुर	ईशानगर	40	चौकी नैनागिर	बकस्वाहा	नैनागिर

2. शर्तें:-

2.1 इस आदेश के तहत धनराशि निम्न मद से दी जाएगी:-

अ. 90 प्रतिशत राशि अर्थात रु. 2 लाख प्रति परिसर के मान से कुल रु. 72 लाख स्वच्छ भारत मिशन मद से।

ब. संस्था अंशदान 10 प्रतिशत अर्थात रु. 20,000 प्रति परिसर के मान से कुल रु. 8 लाख स्वच्छ भारत मिशन के सूचना, शिक्षा एवं संचार मद से।

2.2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर राज्य स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित मानक तकनीकी अवयवों एवं मापदण्डों अनुसार निर्मित किया जाए। स्थानीय परिस्थितियों अनुसार निर्मित क्षेत्रफल व सुविधाएं यथावत रखते हुए रूपांकन में परिवर्तन किया जा सकता है।

2.3 निर्माण एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत होगी।

2.4 मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन, मध्यप्रदेश प्रथम किश्त (50 प्रतिशत राशि) संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में राज्य स्तर से सीधे अंतरित करेंगे।

2.5 पंचायत सचिव द्वारा ई-निगरानी मोबाइल एप से सेल्फी के साथ परिसर का दरवाजा स्तर तक निर्माण पूर्ण होने का फोटो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पोर्टल (geoportal.mp.gov.in) पर अपलोड करने पर दूसरी एवं अन्तिम किश्त (50 प्रतिशत) जारी की जाएगी।

2.6 परिसर के लिए जल की व्यवस्था एवं निर्माण पश्चात संचालन एवं स्वच्छता की व्यवस्था संबंधित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा करना होगा।

2.7 जनपद पंचायत में पदस्थ विकासखण्ड स्वच्छता समन्वयक समय-समय पर निर्माण एजेन्सी को आवश्यकतानुसार सहयोग देंगे।

2.8 निर्माण पूर्ण होने एवं परिसर के संचालित होने के उपरांत ई-निगरानी मोबाइल एप से ब्लाक समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा फोटो पोर्टल पर अपलोड करना कार्य की पूर्णता के प्रमाणीकरण के लिए मान्य किया जाएगा।

2.9 निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना होगा।

2.10 परिसर संचालन एवं स्वच्छता के संबंध में विकासखण्ड स्वच्छता समन्वयक संस्था के कर्मियों का प्रशिक्षण आयोजित कराएंगे।

(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2909/एसबीएम/बी-7/2017 **भोपाल, दिनांक 07.09.2017**

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग भोपाल।
2. संभागायुक्त, सागर संभाग, मध्यप्रदेश।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन।
4. कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, जिला छतरपुर।
7. ओएसडी मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
8. संबंधित सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत को पालनार्थ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के माध्यम से।
9. मैनेजर विभागीय वेबसाइट/पंचायिका।

विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत धनौरा में आँगनवाड़ी भवन निर्माण को मिली मंजूरी

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./निर्माण-138/2017/10477 **भोपाल, दिनांक 04.09.2017**

//आदेश//

जिला छिन्दवाड़ा के विकासखण्ड हर्रई की ग्राम पंचायत धनौरा में एक आँगनवाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

(i) आंगनवाड़ी भवन का निर्माण प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के ज्ञाप क्र. 1278 दि. 23.03.2017 द्वारा निर्धारित मानक रूपांकन एवं तकनीकी अवयव अनुसार कराया जाए। आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(ii) आंगनवाड़ी भवन की मानक लागत रुपये 7.80 लाख है। निर्माण लागत का 60 प्रतिशत (प्रति भवन रुपये 4.68 लाख) जनपद पंचायत, हर्रई में जमा वित्त आयोग एवं स्टाम्प शुल्क की राशि से दिया जाये। शेष 40 प्रतिशत (प्रति भवन रुपये 3.12 लाख) की व्यवस्था मनरेगा के अभिसरण से की जाये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, हर्रई को आदेशित किया जाता है कि जनपद पंचायत के द्वारा प्रदाय की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत (रुपये 2.34 लाख) संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में दि. 6.9.2017 तक अंतरित कर पालन प्रतिवेदन दि. 9.9.2017 को संचालनालय को भेजें। शेष राशि भवन निर्माण छत स्तर तक होने पर प्रदाय की जाये।

(iii) निर्माण एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत होगी।

(iv) निर्माण कार्य का मूल्यांकन विकास आयुक्त के पत्र क्र. 6967/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 दिनांक 01.06.2017 में दिए गए निर्देशों के तहत निर्माण के विभिन्न चरणों पर आधारित होगा।

(v) उपरोक्त ग्राम पंचायत में भवन विहीन आंगनवाड़ी के लिए भवन निर्माण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आंगनवाड़ी भवन विहीन है और आंगनवाड़ी के लिए शासकीय भवन की व्यवस्था नहीं है।

(vi) भवन निर्माण इसी वित्तीय वर्ष 2017-18 में चरणबद्ध समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना होगा।

चरण	समय-सीमा	मानक मूल्यांकन राशि (रुपये लाख में)
प्रथम चरण (प्लिंथ लेवल)	30 अक्टूबर 2017	1.56
द्वितीय चरण (छत लेवल)	30 नवम्बर 2017	1.56
तृतीय चरण (छत डालने पर)	30 दिसम्बर 2017	1.95
चतुर्थ चरण (कार्य पूर्ण होने पर)	30 जनवरी 2018	1.95
पंचम चरण (फिनिशिंग एवं फिटिंग पूर्ण होने पर	28 फरवरी 2018	0.78
योग		**7.80**

(शमीम उद्दीन)
संचालक

शाजापुर जिले की ग्राम पंचायत खामखेड़ा में होगा आँगनवाड़ी भवन का निर्माण

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./निर्माण-138/2017/10479 **भोपाल, दिनांक 04.09.2017**

//आदेश//

जिला शाजापुर के विकासखण्ड शाजापुर की ग्राम पंचायत खामखेड़ा में एक आँगनवाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

(i) आंगनवाड़ी भवन का निर्माण प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के ज्ञाप क्र. 1278 दि. 23.03.2017 द्वारा निर्धारित मानक रूपांकन एवं तकनीकी अवयव अनुसार कराया जाए। आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(ii) आंगनवाड़ी भवन की मानक लागत रुपये 7.80 लाख है। निर्माण लागत का 60 प्रतिशत (प्रति भवन रुपये 4.68 लाख) जनपद पंचायत, शाजापुर में जमा वित्त आयोग एवं स्टाम्प शुल्क की राशि से दिया जाये। शेष 40 प्रतिशत (प्रति भवन रुपये 3.12 लाख) की व्यवस्था मनरेगा के अभिसरण से की जाये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, शाजापुर को आदेशित किया जाता है कि जनपद पंचायत के द्वारा प्रदाय की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत (रुपये 2.34 लाख) संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में दि. 6.9.2017 तक अंतरित कर पालन प्रतिवेदन दि. 9.9.2017 को संचालनालय को भेजें। शेष राशि भवन निर्माण छत स्तर तक होने पर प्रदाय की जाये।

(iii) निर्माण एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत होगी।

(iv) निर्माण कार्य का मूल्यांकन विकास आयुक्त के पत्र क्र. 6967/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 दिनांक 01.06.2017 में दिए गए निर्देशों के तहत निर्माण के विभिन्न चरणों पर आधारित होगा।

(v) उपरोक्त ग्राम पंचायत में भवन विहीन आंगनवाड़ी के लिए भवन निर्माण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आंगनवाड़ी भवन विहीन है और आंगनवाड़ी के लिए शासकीय भवन की व्यवस्था नहीं है।

(vi) भवन निर्माण इसी वित्तीय वर्ष 2017-18 में चरणबद्ध समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना होगा।

चरण	समय-सीमा	मानक मूल्यांकन राशि (रुपये लाख में)
प्रथम चरण (प्लिंथ लेवल)	30 अक्टूबर 2017	1.56
द्वितीय चरण (छत लेवल)	30 नवम्बर 2017	1.56
तृतीय चरण (छत डालने पर)	30 दिसम्बर 2017	1.95
चतुर्थ चरण (कार्य पूर्ण होने पर)	30 जनवरी 2018	1.95
पंचम चरण (फिनिशिंग एवं फिटिंग पूर्ण होने पर	28 फरवरी 2018	0.78
योग		7.80

(शमीम उद्दीन)
संचालक

दमोह जिले की ग्राम पंचायत तिरलाई में होगा आँगनवाड़ी भवन का निर्माण

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./निर्माण-138/2017/10481 **भोपाल, दिनांक 04/09/2017**

//आदेश//

जिला दमोह के विकासखण्ड दमोह की ग्राम पंचायत तिरलाई में एक आँगनवाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

(i) आंगनवाड़ी भवन का निर्माण प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के ज्ञाप क्र. 1278 दि. 23.03.2017 द्वारा निर्धारित मानक रूपांकन एवं तकनीकी अवयव अनुसार कराया जाए। आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

(ii) आंगनवाड़ी भवन की मानक लागत रुपये 7.80 लाख है। निर्माण लागत का 60 प्रतिशत (प्रति भवन रुपये 4.68 लाख) जनपद पंचायत, दमोह में जमा वित्त आयोग एवं स्टाम्प शुल्क की राशि से दिया जाये। शेष 40 प्रतिशत (प्रति भवन रुपये 3.12 लाख) की व्यवस्था मनरेगा के अभिसरण से की जाये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, दमोह को आदेशित किया जाता है कि जनपद पंचायत के द्वारा प्रदाय की जाने वाली राशि का 50 प्रतिशत (रुपये 2.34 लाख) संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में दि. 6.9.2017 तक अंतरित कर पालन प्रतिवेदन दि. 9.9.2017 को संचालनालय को भेजें। शेष राशि भवन निर्माण छत स्तर तक होने पर प्रदाय की जाये।

(iii) निर्माण एजेन्सी संबंधित ग्राम पंचायत होगी।

(iv) निर्माण कार्य का मूल्यांकन विकास आयुक्त के पत्र क्र. 6967/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 दिनांक 01.06.2017 में दिए गए निर्देशों के तहत निर्माण के विभिन्न चरणों पर आधारित होगा।

(v) उपरोक्त ग्राम पंचायत में भवन विहीन आंगनवाड़ी के लिए भवन निर्माण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आंगनवाड़ी भवन विहीन है और आंगनवाड़ी के लिए शासकीय भवन की व्यवस्था नहीं है।

(vi) भवन निर्माण इसी वित्तीय वर्ष 2017-18 में चरणबद्ध समय-सीमा के भीतर पूर्ण करना होगा।

चरण	समय-सीमा	मानक मूल्यांकन राशि (रुपये लाख में)
प्रथम चरण (प्लिंथ लेवल)	30 अक्टूबर 2017	1.56
द्वितीय चरण (छत लेवल)	30 नवम्बर 2017	1.56
तृतीय चरण (छत डालने पर)	30 दिसम्बर 2017	1.95
चतुर्थ चरण (कार्य पूर्ण होने पर)	30 जनवरी 2018	1.95
पंचम चरण (फिनिशिंग एवं फिटिंग पूर्ण होने पर	28 फरवरी 2018	0.78
योग		**7.80**

(शमीम उद्दीन)
संचालक

जनपद पंचायत महू के ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्र. /पं.रा./निर्माण-121/2017/11725 **भोपाल, दिनांक 03/09/2017**

आदेश

जनपद पंचायत, महू के बैंक खाते में उपलब्ध राशि से निम्न तालिका में उल्लेखित ग्रामों में टाईप-1 सामुदायिक भवन बनाने के लिए प्रति भवन रुपये 12.00 लाख (बाउण्ड्रीवाल सहित) के मान से कुल 09 भवनों के निर्माण के लिये रु. 108.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाती है-

क्र.	ग्राम	ग्राम पंचायत
1.	दतौदा	दतौदा
2.	नावदा आदिवासी मोहल्ला	नावदा
3.	कोदरिया खरोल मोहल्ला	कोदरिया
4.	सिमरोल	सिमरोल
5.	जोशी गुराडिया	जोशी गुराडिया
6.	कालीकिराय	कालीकिराय
7.	चोरडिया	चोरडिया
8.	कमदपुर	कमदपुर
9.	सेंडल-मेंडल	

2. शर्तें-

2.1 निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत होगी।

2.2 निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के पत्र क्र. 3773, दि. 14.08.2017 द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों एवं अवयवों के अनुसार करना होगा। प्रमुख अभियंता के इस पत्र में तकनीकी मापदंड नियत कर दिए जाने से पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

2.3 प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने बाउण्ड्रीवाल की मानक लागत रुपये 3,550/- प्रति रनिंग मीटर निर्धारित की है जिसमें गेट की लागत शामिल है। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्धारित तकनीकी अवयवों एवं मापदण्डों के अनुसार करना होगा।

2.4 संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

2.5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आवश्यक समझे तो शासन के किसी भी विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री अथवा वरिष्ठ स्तर के अभियंता से आवश्यकता अनुसार तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मदद की व्यवस्था कर सकते हैं। इस हेतु प्रति भवन, प्रति निरीक्षण पारिश्रमिक तय कर प्रति भवन की स्वीकृत लागत का अधिकतम एक प्रतिशत जनपद पंचायत की निधी से व्यय किया जा सकेगा।

2.6 निर्माण का चरणबद्ध मानक मूल्यांकन प्रमुख अभियंता के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.08.2017 अनुसार मान्य होगा।

2.7 भवन निर्माण दि. 31.03.18 तक पूर्ण कराना होगा।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महू के बैंक खाते में जमा राशि में से उपरोक्त भवनों के निर्माण के लिए प्रथम किश्त 50 प्रतिशत धनराशि निर्माण एजेन्सी को जारी करें। शेष 50 प्रतिशत राशि भवन एवं छत स्तर (लिंटर्न लेवल) तक पूर्ण होने पर जारी की जाए।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(शमीम उद्दीन)
संचालक

जिला/जनपद पंचायतों के अधोसंरचना कार्यों हेतु अनुदान – वर्ष 2017-18

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्र. /61/अमुस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 11.09.2017**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, (समस्त), मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, (समस्त), मध्यप्रदेश।

विषयः- जिला/जनपद पंचायतों को अधोसंरचना कार्यों हेतु अनुदान- वर्ष 2017-18

संदर्भः- विभाग का पत्र क्र./335/475/2016/22/पं-1 दि. 15.12.2016

विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र दि. 15.12.2016 द्वारा जिला पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर लिए जाने वाले अधोसंरचना कार्यों के लिए अनुदान राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई हैः-

1.1 जिला पंचायत के लिए राशि का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा-

अ. जिला पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 25.00 लाख
ब. जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 15.00 लाख
स. जिला पंचायत के अन्य प्रत्येक सदस्य के विकल्प पर राशि रु. 10.00 लाख

1.2 जनपद पंचायत के लिए राशि का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा-

अ. जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए विकल्प पर राशि रु. 12.00 लाख
ब. जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के विकल्प पर राशि रु. 8.00 लाख
स. जनपद पंचायत के अन्य प्रत्येक सदस्य के विकल्प पर राशि रु. 04.00 लाख

2. वर्ष 2017-18 के लिए जिला एवं जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर अधोसंरचना कार्यों के लिए उपरोक्तानुसार स्वीकृति संबंधित जिला पंचायत एवं संबंधित जनपद पंचायत के बैंक खाते में उपलब्ध राशि से प्रदान करने की अनुमति संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत को निम्न शर्तों के साथ दी जाती हैः-

2.1 इस आदेश के तहत जारी की जाने वाली स्वीकृतियाँ पंच परमेश्वर योजना के तहत जारी मानी जाएंगी।

2.2 जिन जनपद पंचायतों के बैंक खातों में जमा धनराशि उपरोक्तानुसार आवश्यक धनराशि की तुलना में कम है उनके बैंक खातों में राज्य स्तर से धनराशि पंचायतीराज संचालनालय से जारी की जाए।

2.3 पंचपरमेश्वर योजना के तहत प्राथमिकताएं विभागीय पत्र दि. 15.12.2016 द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त पेयजल हेतु अधोसंरचना विकास पर भी व्यय अनुमत्य होगा।

2.4 निर्माण एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत हो सकेगी लेकिन पेयजल संबंधी अधोसंरचना के लिए कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की तकनीकी सलाह एवं स्वीकृति बंधनकारी होगी।

2.5 दि. 30 सितंबर 2017 तक जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अधोसंरचना कार्य हेतु उसके विकल्प का

इस्तेमाल नहीं करने की दशा में यह माना जाएगा कि उसने उसका विकल्प समर्पित कर दिया है और ऐसी दशा में वर्ष 2017-18 के लिए संबंधित सदस्य का विकल्प समाप्त माना जाएगा।

3. विभागीय ज्ञाप दि. 28.4.2017 द्वारा जिला पंचायत/जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों के क्षेत्र के संबंध में जारी निम्न निर्देश बंधनकारी होंगे:-

3.1 जिला पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प पर लिए जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला रहेगा।

3.2 जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विकल्प के कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र संपूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्र रहेगा।

3.3 जिला/जनपद पंचायत के शेष सभी निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर लिए जाने वाले कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र उनके निर्वाचित क्षेत्र की सीमा रहेगी अर्थात् संबंधित सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर उनके विकल्प पर आवंटित धनराशि से अधोसंरचना कार्य स्वीकृत नहीं किए जा सकेंगे।

4. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि :-

4.1 दि. 22 से 29 सितंबर, 2017 के मध्य प्रत्येक जिला/जनपद पंचायत की सामान्य सभा आयोजित करने के लिए तिथि नियत कराकर सामान्य सभा की बैठक अनिवार्यतः आयोजित कराएं।

4.2 उक्त बैठक में जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से अधोसंरचना विकास कार्य हेतु विकल्प प्राप्त किए जाएं और बैठक समाप्त होने के 7 दिवस के भीतर आवश्यकतानुसार तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी कराई जाए।

4.3 सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में जिला/जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य का विकल्प प्राप्त किए बगैर इस आदेश के तहत कोई स्वीकृति जिला/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जारी नहीं करें।

5. जिला/जनपद पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के विकल्प पर अधोसंरचना कार्यों हेतु दी गई स्वीकृति की जानकारी विभागीय पोर्टल पर 10 अक्टूबर 2017 तक अनिवार्यतः दर्ज की जाए।

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. /62/अमुस/पंग्राविवि/2017 **भोपाल, दिनांक 11.09.2017**

प्रतिलिपिः-

1. विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. संचालक, म.प्र. पंचायतराज संचालनालय।
3. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारण्टी परिषद।
4. प्रमुख अभियंता/समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।
5. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग